



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. १९१]

नई विल्ली, सोमवार, सितम्बर २४, १९७९/अस्विना २, १९०१

No. 191] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 1979/ASVINA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

शास्त्रिय नागरिक आवृत्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

शास्त्रिय विभाग

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना मंत्र्या ४०-प्राईटी/सीपीएन/७९

नई विल्ली, २४ सितम्बर, १९७९

विषय :- जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई १९७८-७९ के लिए जापानी अनुदान भवायता के अन्तर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आयातों के लिए जापान लाइसेंस जारी करने के लिए शामिल होने वाली नियम तथा शर्तें जो कि परिशिष्ट १ और २ में अलग-अलग दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

विसिल संख्या प्राइटीसी/३९/१८/७८—१९७८-७९ के लिए जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई जापानी अनुदान भवायता वैन २.९ विलियन (यैन २,९००,०३६,०००) के अधीन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आयातों के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के लिए शामिल होने वाली नियम तथा शर्तें जो कि परिशिष्ट १ और २ में अलग-अलग दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

मी० थैंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात नियंत्रण

शास्त्रिय विभाग की सार्वजनिक सूचना मं० ४९ प्राइटीसी पीएन/७९ विनांक २४-९-१९७९ के लिए परिशिष्ट-१

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किए गए १९७८-७९ के लिए २.९ विलियन (यैन २,९००,०३६,०००) के जापान अनुदान भवायता के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें।

बृहं १-मामान्य भारत

(१) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई २.९ विलियन जापानी अनुदान सहायता प्राइटी एक और विकासशील देशों के हक में संगठित की गई है। तदनुसार, इस अहं के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली पर्यावरण और उनसे संबंधित प्रासंगिक सेवाएं जापान और अनुबन्ध-१ की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं। ये वेश इस अहं के अन्तर्गत पात्र स्वतं देव होंगे। लेकिन, यदि लाइसेंस के अधीन आयात की गई पर्यावरण में ऐसे घटक हैं जिनका मूल स्पष्ट से उत्पादन आयात स्वतं देशों से उत्था है तो संभरण ठेके का समझौता बार्ता करते समय आयातको को इस भाग का मुनिष्क्य कर लेना चाहिए कि संभरण ठेके के देश में आयात किए गए ऐसे घटकों का, आयात भूल्क सहित कुल आयात-बीमा-भाड़ा मूल्य संभरण ठेके के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से ३०% से कम है। ऐसे मामले में संभरणों से इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे संभरण ठेके में संलग्न कर देना चाहिए। इस अनुदान सहायता के अधीन जो पात्र मर्दे आयात की जा सकती है उनकी सूची अनुबन्ध में दी गई है।

(२) लाइसेंस पर एक पीर्षक “१९७८-७९ के लिए २.९ विलियन जापानी अनुदान सहायता होगा”। प्रथम और द्वितीय प्रत्यक्ष के लिये लाइसेंस संकेत “एस/जे० एन० होगा”। ये प्रत्यक्ष मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण के आयात लाइसेंस के अधिकारी पवर में भी दुहराये जाएंगे।

(३) बैक लर्च, जिनका प्रेषण मामान्य बैक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विशेषी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता

के कर्मीणन के प्रति कार्ट भी भूगतान अधिकारी को भारतीय रूपये में भारत में चुनाव चाहिए। लेकिन ऐसे भूगतान लाइसेंस मत्य के ही भाग होने और इन्हिये लाइसेंस पर ही प्रमारित किए जाएंगे।

1(4) आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारम्भिक वैध प्रवधि के साथ जारी किया जाएगा। लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंस गारी को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से समर्पक करना चाहिए जो इस मामले में आधिक कार्य विभाग (टी गी एम अनुभाग) से परगमग करेगा।

1(5) पक्के आदेश अनुबन्ध-1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर विए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आधिक कार्य विभाग (टी गी एम अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। “पक्के आदेशों” का आर्य विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन अर्य आदेशों या अर्य संविदाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्थित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों। विदेशी संभरकों को भारतीय अधिकारियों के प्रादेश/और या ऐसे भारतीय अधिकारियों द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकरणीय नहीं है।

1(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शैत का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग, टी सी एम अनुभाग को नहीं पहुंच जाने हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं विए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि यूद्ध इम लाइसेंस के जारी होने की तिथि में 4 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपावाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग (टी सी एम अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको लाइसेंसधारी को प्रेतित करेंगे।

पोन लदान के लिए आविधी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 30-6-1981 के बाब की न हो।

खण्ड-2 संभरण ठेके का समझोता करते समय ध्यान में रखें जाने वाली विशेष बातें:

2(1) (क) ठेके का मूल धेन या यू० एम० डॉलर या पौंड स्टर्लिंग में एक प्रेन एक मेंट या एक पेनी से कम की भिन्न के बिना ही अधिव्ययत होना चाहिए। और इसमें भारतीय अधिकारी का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रूपए में चुकाना चाहिए। भारतीय रूपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अधिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहूज पर्यात निष्पुण लागत, बीमा और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रशिक्षित की जा सकती है परन्तु ठेके में बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का अर्थ यास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निष्पिष्ट किए गए भाड़े का अर्थ यास्तविक छाँचों के अधिकृत देय धनराशि होगी।

(ख) संविदा में नकद आधार पर अर्थात बैंक आप इण्डिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान वस्तावेंजों को प्रस्तुत करने पर भूगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) क्य आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण प्रादेश केवल अग्रेजी में होने चाहिए।

2(2) मूल्य में 30 करोड़ धेन या 15,00,000 यू० एम० डॉलर या 8,00,000 पौंड मूल्य तक (भारतीय अधिकारी के कमीशन को छोड़कर) के अलग-अलग आयातों के लिए लाइसेंसधारी संभरकों से सीधे ही खरीदारी करने के लिए स्वतन्त्र हैं। उसे अनुबन्ध-1 में सूची बदल देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की पृष्ठताठ की आवश्यकता नहीं है।

2(3) लेकिन, जिस मामले में संभरण ठेके के मूल्य उपर्युक्त 2(2) में निर्धारित मीमा से अधिक हो जाते हैं (भारतीय अधिकारी के कमीशन को छोड़कर) तो उसमें अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियायित्यों में से किसी एक का बहुत पूर्वीक प्रत्युभरण करना चाहिए:—

(क) औपचारिक बुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना।

(ख) औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना।

(ग) अनीपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति।

2(4) पात्र स्रोत देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अधिप्राप्ति के किसी भी संदर्भ का अर्थ जैसा भी मामला हो, निविदा अवधि अधिप्राप्ति से होता है। औपचारिक प्रतियोगिक अधिप्राप्ति या प्रत्यक्ष घ्रावेशारी के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि से उन मामलों में छूट दी जा सकती है जिनमें:—

1. पात्र संभरकों की एक विशेष धेन में या देशों की सीमित संख्या में विद्युतान्वय हों।

2. पारस्परिक अखल-अखल का या उपस्कर के मानकीरण का सुनिश्चय करने के लिए या डिजाइन की विशेष आवश्यकताओं के कारण एक विशेष विशिष्टिकरण, व्यापार नाम या पदनाम के संदर्भ में पर्य बस्तु की खरीदारी आवश्यक हो।

3. खरीदारिया आपातकालीन अधिप्राप्ति की श्रेणी में आती हों इसलिए, लाइसेंसधारी को सलाह दी जाती है कि जिस मामले उपर्युक्त पैरा 2(3) के (क) और (ख) की क्रियाविधि का महारा नहीं लिया जा सकता है उसमें आधिक कार्य विभाग को संदर्भ भेजना पड़ेगा जो कि ऐसे प्रत्येक मामले पर पात्रता के आधार पर विचार करेगा।

2(5) जिस मामले में औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने की क्रियाविधि का सहारा लिया जाता है उसमें निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए:—

(क) बोली लगाने के लिए नियंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचालित होने वाली कम से कम एक अखलाकार में विशापित करने पड़ेंगे।

(ख) बोली के आण या बोली लगाने की गारंटी सामान्य आवश्यकता है परन्तु उनको इनना उन्ना महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले हनोस्साह हों जाएं।

(ग) बोली खुल जाने के बाब बोलीकारों को यथाशीघ्र बोली आण या शारटिंग रिशा कर देनी चाहिए।

2(6) आयात लाइसेंस के महे केवल एक संविदा प्रविष्ट की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा गकी है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाब पूर्व मन्मोहन से लेना चाहिए।

2(7) सभरक की पाज़ना :

संभरक पात्र स्वतं देशो का राष्ट्रिक होगा या पात्र स्वतं देश में पज़ीकृत और समाविष्ट न्यायिक अवक्तव्य होगा।

खण्ड-3

भंभरण ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए—

3(1) 1978-79 के लिए 2.9 विनियन के प्रनुदान भाग्यता से सम्बद्ध हम संविदा की व्यवस्था 17 मार्च, 1979 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के प्रनुदान की गई है।

3(2) सभरकों को भुगतान उम्म “भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र” (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1978-79 के लिए जापानी प्रनुदान सहायता के अधीन दैनंदिन और टोकियो के नाम से गहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त भंतालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० आ० बैंक विलिंग, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

3(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए महसूल होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

3(4) उम्म मामले में जिम्में संभरक जापान में स्थित हो और भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श संस्कार की व्यवस्था करने को देत्यार है और उसके लिए सम्बन्धित माल की सुपुर्दी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन लिए 4 मास पहले ही भारतीय दूतावास टोकियो को अधिसूचित करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए। विशेष मामलों में, जहा भारतीय आयातक यह आहता हो तो अधिसूचना की अवधि कम की जा सकती है। आवश्यक ब्यांक देने हुए प्रत्येक पोतलादान के आश जापानी सभरक को आयातक को केवल सूचना भेजने के लिए ही सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

3(5) नीचे सकेनिक प्रपत्र (तीन प्रतियों में) में एक प्रमाण-पत्र—

“मैं (हम) प्रत्यक्षरा यह स्पष्ट करता हूँ/करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी . . . . . [पात्र स्वतं देश] में पज़ीकृत है और पात्र स्वतं देशो के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है या पात्र स्वतं देशो में पज़ीकृत और शामिल हुए न्यायिक व्यवितयों द्वारा नियंत्रित है।”

3(6) यदि किसी मामले में ठेका श्रौपचारिक खुले अन्तर्गटीय निविदा करने या श्रौपचारिक चुनिन्दा अन्तर्गटीय निविदा करने पर आशारित हों तो निम्नलिखित के सम्बन्ध में एक प्रगाण-पत्र भेजना चाहिए—

(1) उम्म सखबार का नाम जिम्में बोली का विशिष्टिकरण प्रकाशित किया गया था।

(2) उन पाटियों का नाम जिन्होंने निविदा पूछताल के प्रति आश्चर्य की।

(3) यह निर्दिष्ट करने हुए कि क्या यह क्रियात्मक रूप में निम्नतम उपयुक्त थोली है, एक विशेष थोली (प्रस्ताव) चुनने का कारण।

टिप्पणी— पर्यावरण की अधिकारित और आपूर्ति भविदा . . . का विस्तृत व्योरा प्रनुदान-2 में देखें।

खण्ड-4- भारत सरकार द्वारा ठेके का प्रनुदान:

4(1) पक्के आवेदन देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर भाइरोमधारी को बोनो पक्कों और विधियत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियों या विदेशी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्य आवेदन और विवेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में उसके पुष्टिकरण की चार प्रतियाँ,

जो सब प्रकार से पूर्ण हों, सम्बन्धित वैध आयात लाईसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित और प्रनुदान-3 में सलग्न प्रपत्र ‘ए/पी’ जारी करने के लिए आवेदन” उपर्युक्त विवाचित्र भविदा में आवश्यक आयांदनों से उत्पन्न सभी मंचिदा सूचनाओं के लिए भी लागू होती है। एक आवेदनपत्र (दो प्रतियों में) के साथ सावध पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हुए भेजने चाहिए।

4(2) यदि ठेके के दस्तावेज, “ए/पी” जारी करने के लिए आवेदन-पत्र और व्यवस्था दस्तावेज मही पाएं जाएँ तो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, टीमी एम अनुभाग ठेके का प्रनुदान करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट को गहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक और भारत के राजदूतावास टोकियो को भेजने की व्यवस्था करेगा।

4(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 बैंक और टोकियो के लिए “भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र” (ए/पी) जारी करेगा। ए/पी की प्रतियो भारत के राजदूतावास टोकियो, आयातक, भारत में प्रायातक के बैंक और टीमी सी एम अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त भंतालय को पठाकित की जाएँगी।

4(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की प्राप्ति के बाद बैंक औफ इण्डिया, टोकियो जापान की सरकार, भारत के राजदूतावास टोकियो, भारत के बैंक के आयातक और महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना में सभरकों अवगत कराएगा।

4(5) पोतलादान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक प्रगते बैकरों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक औफ इण्डिया, टोकियो का प्रस्तुत करेगा। यदि दरनावेज मधी पाए गए तो बैंक औफ इण्डिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित धनराशि को विदेशी सभरक, को उसके बैकरों के माध्यम से रिहा करेगा।

4(6) संभरक के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक औफ इण्डिया टोकियो को देय बैंक खंड भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक द्वारा बैंक औफ इण्डिया टोकियो को प्रेषप द्वारा मामात्य बैंक प्रणोदी से भारत सरकार के लेखे की प्रभावित किए जिन्होंने निर्धारित किए जाएँगे।

खण्ड-5—रपया जमा करने का उत्तरदायित्व :

5(1) मूँ विनियम पात्र परिवहन दस्तावेज लाय हो ताथ वक्त विवेशी के लिए बैंक औफ इण्डिया टोकियो को देय बैंक खंड भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक द्वारा बैंक औफ इण्डिया टोकियो को प्रेषप द्वारा मामात्य बैंक प्रणोदी से भारत सरकार के लेखे की प्रभावित किए जिन्होंने निर्धारित किए जाएँगे।

5(2) विवेशी संभरक को देय बैंक द्वारा भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक औफ इण्डिया टोकियो को देय बैंक खंड भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक द्वारा बैंक औफ इण्डिया टोकियो को देय बैंक द्वारा भुगतान की व्यवस्था के लिए विवेशी संभरक का बैंक औफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की व्यवस्था के लिए से वाल्सिक रुपया जमा करने की नियत नहीं ही की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए ० ९ प्रतिशत प्रतिवर्ष को दूर से और शेष अवधि के लिए १५ प्रतिशत का दूर से हिसाब लगाकर व्याज मायनिक सूचना सं०-४६ आई टी सी (पो एन)/७६, दिनांक १६-६-७६ के अनुसार गरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है। व्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विवेशी संभरक को भुगतान किया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है। देय शायद सार्वजनिक सूचना सं० १०३-आई टी सी (पी एन)/७६ दिनांक १२-१०-७६ द्वारा प्रायोगित सार्वजनिक सूचना सं० ७४-आई टी सी (पी एन) ७४ दिनांक ३१-५-७६ भुगतानों की येत धनराशि के वरावर ६८ पयों की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनियम दर मुख्य

नियत्रक, आयात-नियरित की सार्वजनिक सूचना सं०-आई टी सी (पी एन) /76 दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनियम को सिक्षित दर होगी या वह दर होगा जो कि मुद्रा नियत्रक, आयात-नियरित की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिषद्को के माध्यम से सरकार द्वारा समय-पमय पर अधिसूचित की जाए। इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे हो आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चय करने का उत्तराधायित्व मम्बद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात वस्तावेत्र आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेख में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से वस्तावेत्र लेख में पहले ही देय धनराशि लेख में सही रूप से जमा कर दी गई है। जिस लेख मीर्ये में उपर्युक्त रूप से जमा करना चाहिए वह “के डिपोजिट्स एण्ड एक्सान्सेज 843 मिलियन डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फोर परेंजिंग एटसेक्ट्रा एक्साड परेंजिंग परेंजेस ग्राट एंड फास गवर्नरमेंट जापान फार 1978-79” (येन 2.9 विनियन ग्राट एंड)

5(2) उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी रुपयी में सरकार की माल में नकद जमा होनी चाहिए, या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसके उपर्योग की भी भी गणद्वयकृत बैंक (हुन्डीकर्ता) से प्राप्त एक दुन्ही (डिमान्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (दुन्ही ग्राहक और प्रापक) की सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई टी सी (पी एन) 68, दिनांक 30-8-1968 सं० 233-आई टी० सी (पी एन) /68, दिनांक 24-10-68, सं० 132-आई टी० सी (पी एन) /71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई टी सी (पी एन) 74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई टी सी (पी एन) 76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेख में जमा करने के लिए धन प्रेषण करना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ऐसो मांग किए जाने के बाद मात्र यिनी के भीतर मम्बद्ध भारतीय बैंक भी उत्तर निर्धारित तरीके से वह अनियक्त धनराशि सेवा खबरों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। खासान के विभिन्न कॉलमों को भरते समय आयातकों उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई टी सी (पी एन) /76 दिनांक 12-10-76 के साथ पहली जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई टी सी (पी एन) /71 दिनांक 5-10-71 के पश्चा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन) 74, दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम “धन प्रेषण और, प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण व्यौद्धे” में नियन्त्रण रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खासान चालान में नियन्त्रित व्यौद्धे नियन्त्रण रूप से प्रस्तुत करने चाहिए।

(क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निषेद किए जाने हैं

(ग) विदेशी सम्बरक को भुगतान करने को तिथि।

(घ) चुकाए गए व्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना गया है

(ङ) जमा की गई कुल धन राशि

(व्याज की गणना विदेशी सम्बरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेख में भमतुत्प रूपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जानी है।)

उसके पश्चात् सीएए द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संवर्ध देने हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को मन्त्रन

करने हुए खालान रूपया जमा करने का साक्ष देने हुए पंजीकृत दाक द्वारा सीएए को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी :—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रूपया का निषेद बैंक आफ इण्डिया टोकियो से आदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत लदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर नियन्त्रण रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल आव सीएए वित्त मंत्रालय (प्राधिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

5(5) भारत में सम्बद्ध बैंक आफ इण्डिया को लाइसेस की मुद्रा विनियम नियवण प्रति पर संपादन की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अप्रीत्वानी “प्रम” प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ ब्रॉडबैंड को भेजना चाहिए।

खण्ड 6 विविध शर्तें

6(1) आयात लाइसेस के उपयोग की रिपोर्ट

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोत लदानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के संबंध में घोर जो पोत लदान होने वाली है उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट भी एएए प्राधिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय यू सी शो बैंक विलिंग मपद मार्ग नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

6(2) सम्भरकों का विशेष शर्तें अधिसूचित करना

लाइसेसधारी का चाहिए कि वे आयात लाइसेस को उत्तर विशेष शर्तों से सम्भरक का प्रवर्गन कराके जो समझीन का पालन करने में सम्भरको पर प्रभाव दाल सकती है।

6(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेसधारी और सम्भरकों के बीच यदि काई विवाद उठा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तराधायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इण्डिया टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों माफ माफ “भुगतान के नियम” के अधीन अनुबंध-1 में वर्णित जानी चाहिए। विवादों से निपटने की शर्तें ऐके की शर्तों में जामिल होनी चाहिए।

6(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या मधी मामलों से सम्बन्धित जापान से 1978-79 के लिए मनुदान सहायता के अधीन सभी आमारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-पमय पर जारी किए निदेशी या मनुदेशों पा आदेशों का लाइसेसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

6(5) अनिकमण या उल्लंघन

6(6) अनुबंधों की सूची

उपर्युक्त खंडों में स्थिर की गई शर्तों के अतिकमण या उल्लंघन करने पर आयात नियरित (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

आनुबंध—1 पात्र स्ट्रोन देपों की सूची

आनुबंध—2 पात्र पर्य बम्पुओ की सूची

आनुबंध—3 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र।

आनुबंध—4 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का प्रपत्र।

आनुबंध—5 मान की आधिप्राप्ति की विस्तृत क्रियाविधि।

## अनुष्ठान—1

(मर्यादा खण्ड—1 कठिका 1(5))

पात्र स्त्रीत देशों की सूची

(क) आई और ई द्वारा देश

आस्ट्रेलिया  
आस्ट्रिया  
बेल्जियम  
कनाडा  
डेनमार्क  
फिनलैण्ड  
फ्रान्स  
जर्मनी संघीय गणराज्य  
यूनान

प्राइसलैण्ड

हाईस्लैण्ड

जापान

प्रायरलैण्ड

लंडन

नीदरलैण्ड

न्यूजीलैण्ड

नार्वे

स्लीडन

स्विटजरलैण्ड

त्रुकी

यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य

(ख) विकासशील देश नथा उसके क्षत्र

(ख-1) नाम-ओ० पी० ई० सी० विकासशील देश

1 अफ्रीका उत्तरी महारा

मिश्र

मारोको

तुनीशिया

2 अफ्रीका, दक्षिणी महारा

एगोना

बोत्सवाना

बरन्डी

केवेरन

कैप बडो द्वीप समूह

केन्द्रीय अफ्रीकन गणतन्त्र

चाद

कमोरो द्वीप समूह

हथापिया

जाम्बिया

कापो, वर्मोह गणराज्य

इक्वेटोरियल गाईता

धाना

गिनी

ग्राइबरी कोर्ट

कीनिया

लेमोथे

लाइबेरिया

मालियार्मी गणतन्त्र

मलावी

माली

मालिनिया

मारीणस

मौजाम्बोक

नाइगरा

पुर्तगाली गिनी

रियुनियन

रोडेनिया

रवान्डा

मट केनिया और डेम (2)

माशोटोम और प्रिन्साइप

मेनेगान

मेजिलिज

सियरा लिन्प्रोस

मोमालिया

सूडान

स्वाजीलैण्ड

टेरो ग्रान्डम और इल्साम

टोगो

युगान्डा

तजानिया गणराज्य मध्य

अपर बोल्डा

जाम्बो गणतन्त्र

जाम्बिया

3 अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय

बेहूमस

बार्टांडोज

बे नाइज

बर्गुडा

कोस्टोरिका

क्यूशा

डोमिनिकन गणराज्य

एल साल्वेदोर

गुवाइलोप

ग्वाटेमाला

हैती

हान्ड्राम

जेमेका

माटिनिक

मैक्सिको

नीदरलैण्ड एनटिलीज

तिकारागुदा

पनामा

(1) पहले सेनी गिनी का प्रदेश, फरनेन्ही पी द्वीप सहित

(2) निम्नसिखित द्वीपों सहित --

प्रसेन्यान, द्रिस्टन डाइन एसेसिवित्स, माइटिगेस एफ

(3) मुख्य द्वीप समूह, अर्जेणा, बोनाहरे क्युराकाओ साहा,

सेन्ट मारटिन

(रक्षण भाग)

सेन्ट सिपरी मिकेलोन

द्रिनिडाइ और टोबूगो

सेन्ट इन्डीज (शावा) एन० आई० ई०

(क) सम्बन्धित राज्य (1)

(ख) आधित (2)

4. दक्षिणी अमरीका	न्यूहेसिसेस (त्रिं और फे)
अजन्टीना	लियू
बोलिविया	प्रेसिपिक द्वीप समूह (मधुक गज्य) ( 6 )
आजील	पापुवा न्यू गिनी
चिली	नोलामन द्वीप समूह (त्रिं)
कोलिम्बिया	टॉनो
फाल्कलैंड द्वीप समूह	वानिस और फूतुना
फालिसी गिनी	पश्चिमी ममाओ
गुयाना	9. यूरोप
पाराग्वे	साइप्रेस
पीरू	जिब्राल्टर
सूरिनाम	ग्रीक
उरुग्वे	माल्टा
5. मध्य पूर्वी एशिया	म्पेन
अहरीन	तुर्की
हज राइल	यूरोप्लाविया
जोर्डन	( अ-२ ) अंगू० पी० हू० नी० के संबंध या महायोगी देश
लेबनान	प्रल्लीरिया
ओमन	बोलिविया
मिरिआई अरब गणतन्त्र	लीबियाई अरब गणतन्त्र
यूनाइटेड अरब इमिरात	गेब्रान
यमन अरब गणतन्त्र ( 3 )	नाइजीरिया
यमन जनवादी द्वी० आर ( 4 )	हैक्योडोर
6. दक्षिणी एशिया	बेनजैएला
अफगानिस्तान	हैरान
बोगला देश	हैराक
भूटान	कुर्वन
बर्मा	कात्तार
मालद्वीप	सऊदी अरब
नेपाल	मावू धावी
पाकिस्तान	हज्जोनेशिया
श्रीलंका	( 1 ) मुख्य द्वीप एन्टिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेल्ट किट्स ( सेन्ट क्रिस्टोफे ) नेविस भगुड़ा, सेन्टलुकिया और सेन्ट विसेन्ट ।
7. मुगुर पूर्वी एशिया	( 2 ) मुख्य द्वीप मोत्ससरन, सेमान, तुक और शाहकोम और बिटिश बरजिन द्वीप समूह ।
बल्डी	( 3 ) अजमान, ड्रव्या, पुर्जाइरड, राय अन सेनाठ गारजाह और उम अल क्यैन ।
हुगकांग	( 4 ) अदन और विभिन्न मुलनत और असीरन महित ।
खमेर गणतन्त्र	( 5 ) मोमायटी द्वीप (माहिरी सहित) को शामिल करते हुए, प्रास्ट्रल द्वीप समूह, दुमामोट, जाम्बियर ग्रुप और माकेसन द्वीप समूह ।
कोरिया गणतन्त्र	( 6 ) पैसिक द्वीप समूह का डम्प प्रवेश कागोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर) ।
लाओस	प्रानुभ्व—२
माकान्दो	पात्र पाय मूचे
मलेशिया	1. रोल्ज
फिलिपाईन	2. विशेष इस्पात और मिश्रातु इस्पात सहित इस्पात
सिगापुर	3. ट्रॉका और ट्रैक्टरो के विनिर्माण के लिए मष्टक, मवाज़क और पुर्जे
ताइवान	4. रमायन
थाइलैंड	5. भारत-जापान समुक्त उद्यम के लिए फालू पुर्जे, मष्टक और कच्चा माल
तिमोर	
बियतनाम गणतन्त्र	
बियतनाम जनवादी गणतन्त्र	
8. ओसिनिया	
कोक द्वीप समूह	
फिजी	
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप	
फ़ालिसी पोलिनेशिया ( 5 )	
तोरू	
स्पूकोलोडोनिया	



2. भायातक का बैंक ..... उनसे निवेश किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शांति से दूसरी दूसरी प्राप्त करने पर विदेशी संभरको को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करे। संभरको को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपया की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या ४-आई० टी० सी० ( पी० एन० ) / ७६ दिनांक १७-१-७६ या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार जापानी संभरको को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचालित परिवर्तन की मिथित दर पर की जाएगी। संभरक को भुगतान करने की निधि से सरकार के लेवे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० ४६ आई० टी० सी० ( पी० एन० ) / ७६ दिनांक १०-६-७६ के अनुसार पहले ३० दिनों के लिए ९ प्रतिशत वार्षिक दर पर और हमसे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए १५ प्रतिशत की दर से अब्द भी सरकारी लेवे में जमा करना होगा। अब्द दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको जापानी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेवे में रुपया निषेष किया जाता है। ( इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरत उसकी सूचना वी जाएगी ) यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भायातक को सीमा-शुल्क निकासी के लिए भायातक दस्तावेजों का मूल सेट विए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियों या तो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसकी अनुसंधानी संख्याओं या किसी भी राष्ट्रीय बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली-६।

( भाइशित और भायातक ) के नाम में भी उसको देय दशों हजारी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० २३३ आई० टी० सी० ( पी० एन० ) / ६८ दिनांक २४-१०-१९६८, संख्या-१३२ आई० टी० सी० ( पी० एन० ) / ७१ दिनांक ५-१०-७१ संख्या-७४ आईटीसी/पीएन/७४ दिनांक ३१-५-७४ और संख्या-१०३ आई० टी० सी० ( पी० एन० ) / ७६ दिनांक १२-१०-७६ की शर्तों की ओर दिया जाता है। अंका योर्ड जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसेज -८४३ निविल इंपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परेजिस एटमेंट्स एक्स्चूप-परेजिस ग्रान्ट में ह फार दि गवर्नर्मेंट आफ जापान फार १९७८-७९ ( येन २.९ बिलियन एड )।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इण्डिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या -१३२ आई० टी० सी० ( पी० एन० ) / ७१ दिनांक ५-१०-१९७१ के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें जालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना इष्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अप्रेषण पत्र महिन उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जायेगी।

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,  
वित्त मंत्रालय ( अर्थिक कार्य विभाग )  
पहली मंजिल, य० सी० आ० बैंक बिल्डिंग  
संसद भवन, नई दिल्ली ।

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर सकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक २४-१०-६८ में यथा उल्लिखित दशों हजारी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में अब्द की चुकाई गई धनराशि और यिस प्रवधि के लिए अब्द की गणना की है उसके माध्यम जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा अधिकार इस विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खातों सहित यदि कोई हो तो, बैंक खाते और बैंक आफ इण्डिया टोकियो शांति के अन्य खाते इण्डियन बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो

5. अबर मचिव ( टी० सी० एम० ) शाखा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।

अनुदान-५

जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत पथ्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्ज वर्षा।

### 1. प्रस्तावना

जापान सरकार द्वारा प्रदान की गई २.९ बिलियन येन की अनुदान सहायता को रकम हय मार्ज वर्षा में निर्धारित अधिप्राप्ति की क्रियाओं के अनुसार उनकी आनुषांगिक पथ्य वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए पात्र स्थान देशों के बीच कार्य कृत्यालय के लिए और बिना किसी भेदभाव के ध्यानपूर्वक उपयोग की जाएगी।

### 2. अधिप्राप्ति क्रियाविधि का चयन

अनुदान सहायता के अन्तर्गत सूचीबद्ध पण्यवस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियाविधियां लागू होगी :—

- ( १ ) शोपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा देना
- ( २ ) शोपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय संविदा देना
- ( ३ ) अनोपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति
- ( ४ ) मीटी खारीद

( क ) सरकार और/या सरकारी अधिकारण द्वारा अधिप्राप्ति के मामले में शोपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा या शोपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू होगी।

( छ ) गैर-सरकारी अधिप्राप्ति के मामले में उपर्युक्त उल्लिखित कोई भी क्रियाविधि लागू हो सकती है।

( ग ) अनोपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति या सीधी खारीद के माध्यम से ऐकिन इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में अधिप्राप्ति को स्वीकार करना सम्भव है।

- ( १ ) संविदा की शर्तों के अनुसार जहा प्रस्तावित संविदा की अन्तर्गत ३००,०००,००० येन १,५००,००० य० एम० डालर या ८००,००० पौंड स्टालिंग से अधिक नहीं है।
- ( २ ) जहा भाईरक संभरको की संव्या सीमित है।
- ( ३ ) जहा अन्तर्वेदली या उपकरण के मानकीकरण का सुनिश्चय करने के लिए विशेष विशिष्टिया, देह नाम या पदनाम के संवर्ग में या विशेष डिजाइन की आवश्यकताओं के कारण पथ्य वस्तु की खारीद करनी है।
- ( ४ ) जहा या तो क्रियाविधि अथवा क्रियाविधि ( २ ) या उपर्युक्त ( १ ), ( २ ) और ( ३ ) से भिन्न किसी कारण से ( उदाहरणार्थ आपात कालीन अधिप्राप्ति ) क्रियाविधि के लिए लागू नहीं समझा जाएगा।

( घ ) उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी मामले में भायातक इस छंड के १-३ में निर्धारित अधिप्राप्ति क्रियाविधि के अनुसार अधिप्राप्ति की पक्षता से सम्बन्धित कर्जवार की पुष्टि प्राप्त करेगा।

### 3. संविदा की शर्तें :—

इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत विस्तृप्त किए जाने वाली कोई भी संविदा निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी।

### 1. पण्यवस्तुओं की शर्तें

चूंकि इस अनुदान सहायता का उपयोग पात्र स्थान देशों में उत्पादित सूचीबद्ध पण्यवस्तुओं के लिए खचों का वित्तान करने के लिए सीमित है इसलिए संविदा विषयक मद पात्र स्थान देशों में उत्पादित सूचीबद्ध पण्यवस्तुएं हींगी और पात्र स्थान देशों में भारतीय पत्रकों को भेज दी जाएगी यदि पात्र स्थान देशों से भायातक भाग निम्नलिखित फार्मूले से तीस

प्रतिशत ( ३० प्रतिशत ) कम है तो सूचीबद्ध पर्यवर्तनुएं विद्वान की जाएगी भले ही वे संविदा की मद्दों में सूचीबद्ध पर्यवर्तनुओं के प्रथम के रूप में गैरपाल ज्ञान देशों से आयातिन भाग के रूप में शामिल की गई है। ऊपर उल्लिखित फार्मूला—

आयातिन शीमन + आयात शुल्क

× 100

ममरक की जहाज पांच विशुल्क कीमत

३ नभरक की ज्ञाने

ममरक पाल ज्ञान देशों का राष्ट्रिक होगा, या पाल ज्ञान देशों में प्रजीकृत न्यायिक व्यक्ति होगा।

३ आयातक की ज्ञाने

ममरक सेना या उससे मान्यता प्राप्त भारतीय नस्ताओं द्वारा किन्हीं भी पर्यवर्तनुओं की अधिप्राप्ति अधिक के अन्तर्गत पाल होगी।

४. मूद्रा का मन्त्र बंग

विविद क्रमसंख्या एक वेन ( शाई १ ०० ), एक सेन्ट ( सी० १ ०० ) या एक पैसी ( शी० १ ०० ) से कम किसी भिन्न के बिना ही जापानी येत, यूनाइटेड स्टेट डाकर या स्टॉलिंग पौष्ट में निर्वाचित की जायेगी और दैश होगी।

५ संविदा का मानक प्रपत्र

(क) इस प्रत्युत्तान सहृदयता के अन्तर्गत विद्वान की जाने वाली विविद में निम्नलिखित मर्दे शामिल ही जायेगी :—

(१) ममरक और आयातक का नाम और गणिकता

(२) संविदा की मंजुरा और दिनांक

(३) पर्यवर्तनुओं का नाम और मूल ज्ञान

(४) संविदा का मूल मूल्य और मात्रा

(५) अदायगी की ज्ञाने

(६) मृगतान और पोनवदान मनुसूची

(७) मन्त्र सामान्य विनियमन

(ख) दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संविदा या विद्वी संभरक द्वारा विधिवत रूप से पुष्टि भादेश द्वारा समर्थित विद्वी संभरक को भारतीय आयातक द्वारा दिये गये विकल्प भादेश, या उनकी फोटो प्रतियां भी रखी जायेंगी।

(ग) पाकिस्तान की निम्नलिखित विवरण संभरक द्वारा प्रत्येक संविदा में शामिल किया जायेगा।

“मैं (हम) एतद्वारा उल्लेख करता हूँ करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी ..... ( पाल ज्ञान देश ) में पंजीकृत है।”

(८) मृगतान

प्रत्येक मृगतान मनुदान गहायता पर हस्ताक्षर करने की सारी अपर्याप्ति १७ मार्च, १९७९ को या बाद में किया जायेगा। सिद्धांत के रूप में, संभरक की पोनवदान की पूरी अनुशासि संबंधित पोन परिवहन दबस्तावेजों को अस्तुत करने के प्रत्येक मध्य वैक आफ इडिया, टोकियो नकदी के रूप में अर्थ ही आएगी।

४. अन्तर्राष्ट्रीय संविदा का टेंडर देना

जब अन्तर्राष्ट्रीय विविदा जागृ की जाये तब मन्त्र नियमों के मात्र निम्नलिखित नियमों के अनुसार आयातिन की जावेगी—

६५० CI/79-2.

( १ ) विज्ञापन वेकर

श्रोपचारिक बूली अन्तर्राष्ट्रीय विविदा करण के अधीन सभी संविदाओं में ओली मानने के लिये भारत में सामान्यता रूप से प्रकाशित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में विविद की जायेगी।

( २ ) बोलियो के मानने और उन्हें प्रस्तुत करने के बीच के सबसे का अन्तराल।

बोली तैयार करने के लिये अनुमित समय बहुत बड़ी सीमा तक संविदा के महत्व और ऐचौदी के ऊपर निर्भर करेगा। सामान्यता अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिये कम से कम ३० दिनों स्वीकृत किये जाने चाहिए। किन्तु, अनुमित समय प्रत्येक संविदा से मंबधित हाश्वतों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

( ३ ) बोली बोलने की क्रियाविधि

बोलियो की प्रतिम पावसी के लिये श्रीर ओली बोलने की तिथि, गमय और स्थान की ओली आमंत्रण में ओवित किया जाना चाहिए और सभी बोलियो निर्धारित समय पर बूले आम बोलनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियो को बिना बोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने मनुरोध किया है या उन्हें भनुमति दें दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियो की कूप घनराश जोर से पड़ी जानी चाहिए और उनको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

( ४ ) बोली बाल प्रथवा गारंटिया ।

बोली करने के सामने में, बोली बाल या बोली की गारंटियों साथारण आवश्यकताएँ हैं, किन्तु इन्हें उन्हें स्तर पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए जिससे उपयुक्त बोलीकार निश्चात्तित हो जाये।

बोली बाल या गारंटियों बोली बुल जाने के बाद याचाशीष ममफल बोलीकारों को गिरा कर देनी चाहिए।

( ५ ) मापदण्ड

यदि उत्तर राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है, त्रितके अनुसार ही उपकरण या भाल है तो विजिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि आयात धोयांगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किये गये अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पर्यवर्तनुओं की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिपित्य करती है उन्हें भी स्वीकार कर दिया जायेगा।

( ६ ) बाल नामों का प्रयोग

यदि विकेव प्रकार के कालतु पुजों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ आस प्रावश्यक विशेषताओं को अनाये रखने के लिये मानकीकरण की एक हित्री की आवश्यकता है तो विजिष्टिकरण निष्पादन अमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें एक केवल बाल, सूची स० या विशेष विनियमों के उन्होंनों को निर्धारित करना चाहिए। बाल वाले मानने में विजिष्टिकरण को उन विकल्पी पर्यवर्तनुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती जूली है और कम से कम उन विजिष्टिकरण के बराबर निष्पादन और गुण उमरें हैं।

( ७ ) गारंटी और निष्पादन बाल

यदि आवश्यक हो तो बोली संबंधी दस्तावेजों में गारंटी के सिइ जमानत के रूप में कोई प्रपत्र होना चाहिए। यह जमानत या वो बोल गारंटी बाल या निष्पादन बाल द्वारा दी जा सकती है।

( ८ ) निर्धारित शति

यदि आवश्यक हो तो जब कभी सुपुर्दी में कालतु रख्य होता है, राजस्व को हानि शा या आयातक वे लिये अन्य भाग की हानि हो तो बोली संबंधी क्षतिवेजों में निर्धारित शति वाक्यांश जोड़े जाने चाहिए।

## 9. विवरण विधियां (फोर्म ईज्यूर)

बोर्डी दस्तावेजों में शामिल की गई मविदा की गती में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करने हुए हम सम्बन्ध में ब्राक्याश होने आहिए कि मविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने दावितों को न पूरा करना उस हालत में एक चूक नहीं माना जायेगा यदि ऐसी चूक विवरण विधियां (फोर्म ईज्यूर) के फलस्वरूप हुई हैं "मविदा को शतों में इसकी परिचाण दी जानी है।

## (10) शगड़ों का निपटान

शगड़ों के निपटान में मंवंधित व्यवस्थाएँ संविदा की शतों में शामिल की जानी चाहिए। यह बोलनीय है कि व्यवस्थायें अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य में भूल द्वारा बनाये गये "समझौते और मध्यस्थ नियंत्रण के नियमों" या भारतीय एवं समझौते के संभरक दोनों को स्वीकार्य होने वाली व्यवस्थाओं पर आधारित होने चाहिए।

## (11) सूच्याकृत

वाणिज्य विभाग का सार्वजनिक सूचन संब्धा 49 आईटीमी (विएन) /74, दिनांक 24-9-1974 का परिचय 2।

आपान सरकार द्वारा प्रबोन्ह किए गए 1978-79 के लिए 2.9 वित्तिय वेत और आपानों प्रबुद्धान सहायता के अन्तर्गत विभीत क्षेत्र के प्राप्तताएँ के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें

## बाण्ड 1—सामान्य घटें

1. (1) आपान सरकार द्वारा प्रबोन्ह किए गए 2.9 वित्तिय वेत की जापानी प्रबुद्धान सहायता नीरीसीडी और विकासशील देशों के लिए अन्धनमुक्त है। तथनुसार, इस प्रबुद्धान सहायता के अधीन अधिग्राहक की जाने वाली पर्यवस्थाएँ और उनसे सम्बन्धित प्रासादिक सेवाएँ जापान और अनुबन्ध 1 का सूची में उद्दूत सभी देशों में आयात की जा सकती है। ये देश इस प्रबुद्धान सहायता के अन्तर्गत पात्र स्वीकृत देश होंगे। लेकिन, यदि लाइसेंस के अधीन आयात की गई पर्यवस्थाएँ में ऐसे अटक हैं जिनका मूल रूप से उत्पादन आयात क्षेत्र देश या देशों में हुआ है तो मध्यरण ठेके की समझौता वार्ता करने समय आयातक की इस वात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि संभरण ठेके के देश के आयात किए गए तर्फे अटकों का आयात मूलक महित कुल लागत बीमा, भाड़ा मूल्य संभरण ठेके के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से 30 प्रतिशत से कम है। तर्फे मामले में सभरकों में उस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे संभरण ठेके में संभरन कर देना चाहिए। इस प्रबुद्धान सहायता के अन्तर्गत आयात की जाने वाली पात्र पर्यवस्थाओं की सूची प्रबुद्धन्ध 2 में दी गई है।

1. (2) साइमेंस पर एक शोर्पे 1978-79 के लिए 2.9 वित्तिय वेत जापानी प्रबुद्धान सहायता होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस कोड "एस/जे/एन" होगा। ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रित के व्यापार लाइसेंस के प्रयोगपत्र में भी दृष्टिगत जाएं।

1. (3) वे बैंक खर्च जिनका परेण्य समन्वय वैक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी परेण्य की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जायगी। भारतीय अधिकारी के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अधिकारी ने नहरेंग रूपां में भारत में भुगता चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए, साइमेंस पर ही प्रमाणित किए जाएं।

1. (4) आयात लाइसेंस लागत-बीमा भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारम्भिक वैध अधिकारी के भाग जायेगा। लाइसेंस की वैधता में बृद्धि के लिए लाइसेंसधारी की सम्बद्धता लाइसेंस प्राधिकारी में संभरक करना चाहिए जो इस मामले में आधिक कार्य विभाग (टीसीएम अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1. (5) पक्षे प्रावेश प्रबुद्धन्ध 1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों की लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर या लागत

और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे प्रायात लाइसेंस बारी होने की तिथि में 4 महीनों की अवधि के भीतर आधिकारिक कार्य विभाग (टीसीएम अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली की ओर दिए जाने चाहिए। 'पक्षे प्रावेश' का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस धारी द्वारा दिए गए उन व्रत चार्टेशों या काय सविशेषों से है जो भारतीय नाइसेंसधारी से प्राप्त प्रावेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्थित हो या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्थित हो। विदेशी संभरकों के भारतीय अधिकारीयों के आवेदन प्रौद्योगिकी एवं भारतीय अधिकारीयों द्वारा पुष्टिकरण आवेदन स्वीकारणीय नहीं है।

1. (6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस वार्ता का तब तक प्रबुद्धान किया गया नहीं ममका जाएगा जबकि कि ठेके के पूर्ण इमारेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मकालय, प्राधिक कार्य विभाग, (टीसीएम अनुभाग को नहीं पहुंच जाने हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पक्षे प्रावेश वार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर प्रावेश अद्यो नहीं दिए जा सकते का उल्लेख करने हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस की सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। प्रावेश देने की अवधि में बृद्धि के लिए तर्फे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पालता के आधार पर विचार किया जाएगा वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए बृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि बृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि में 8 महीनों से प्रधिक के लिए आगी जारी है तो ऐसे प्रस्ताव निरपेक्ष रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मकालय, प्राधिक कार्य विभाग (टीसीएम अनुभाग), नार्थ ब्लाक, न दिल्ली की ओर जाएं जो कि ऐसी बृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पालता के आधार पर विचार करेंगे और अपना नियंत्रण लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी की प्रेरित करेंगे।

पोलिदान के लिए आविरो विवि विशित करने में इस वार्ता का व्यापार व्यवना चाहिए कि यह तिथि 30-6-1981 के बाद की न हो।

बाण्ड 2—सम्भरण ठेके का समझौता करते समय व्यापार में रड्डी जाने वाली विशेष घटतें

2. (क) ठेके का मूल्य येत या यू०एस० डालर या पौँड स्टर्लिंग में एक येत, एक बेट्ट या एक पैनी से कम की मित्र के बिना ही प्राप्तियां होना चाहिए, और इसमें प्रारंभी अधिकारी का कमीशन, यदि कोई हो तो वह आमिल नहीं होना चाहिए, जो कि प्रारंभी व्यापार में चुकाना चाहिए प्रारंभी रूपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी प्रस्तुति में अधिकतम नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत, बीमा और भाड़ा अनराजि अन्यान्य अलग-अलग प्रदर्शित की जा रक्खती है परन्तु ठेके में यह वात अलग रूप देनी चाहिए कि भाड़े का रूपां वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निश्चित किये गये भाड़े का खर्च वास्तविक रूपों के अनुरिक देय अनराजि होगी।

(ख) मविदा में नकद भुगतान की अवस्था हो तो चाहिए प्रथम जापानी संभरको द्वारा बैंक भाफ इम्डिया, टौकियो के पोनस्वान लस्तावेज प्रस्तुत करने पर।

(ग) अब भाइंग और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आवेदन के बारे में होने चाहिए।

2. (2) मूल्य में 30 करोड़ येत या 15,00,000 यू०एस० डालर या 8,00,000 पौँड मूल्य तक (प्रारंभी अधिकारी के कमीशन को छोड़ कर) के अलग-अलग आयातों के लिए साइसेंसधारी संभरकों से सीधे ही लाइसेंसधारी करने के लिए स्वतंत्र है जब अनुबन्ध 1 में सूचीबद्ध वेष्टों से अन्यान्य विवदा की पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।



बैंक गारन्टी येन धनराशि के तूल्य रूपमें प्रदर्शित करते हुए उस धनराशि के लिए होनी चाहिए जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकरण-पत्र संभाला गया है और इसमें अनुबन्ध-6 में यथा उल्लिखित व्याज तथा श्रव्य वर्षे भी सामिल होने चाहिए। परिवर्तन की वर राजस्व तथा बैंक विभाग द्वारा अधिसूचित भुगतान विनियम की दर पर और भुव्य नियशक, आयात-नियरति द्वारा अधिसूचित की गई सार्वजनिक सूचना संख्या-7 आई टी (पीएन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि की प्रवर्तित भुगतान विनियम की दर पर होगी। यह वर वेतन लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारन्टी की मूल्य की गणना करने के उद्देश्य के लिए है। आयातों की आयत के लिए संग्रहारी लेखों में रूपया जमा करने के उद्देश्य के लिए तुल्य रूपये की गणना नीचे खण्ड-7 में विविध तरीके से करनी होगी।

5(3) यदि ठेके के वस्तावेज भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदनपत्र बैंक गारन्टी और श्रव्य गम्भीरति वस्तावेज सही पाए जाएंगे तो किन मकालय, प्राधिक कार्य विभाग, दीसीएम अनुभाग ठेके का अनुमोदन करेगा और दसावेज का एक सीट नियशक महायता लेखा व लेखा परीक्षा, वित्त मकालय, य०सी०प्रो बिल्डिंग, पहली मजिल, मसद् भाग नं०८ शिल्पी और भारतीय दूतावास, टाकियों का भेजेगा।

खण्ड-6—सम्बन्धित सभरको यो भुगता-भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र

6(1) उपर्युक्त खण्ड-5(3) में उल्लिखित वस्तावेजों के प्राप्त होने पर नहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियशक, प्राधिक नार्य विभाग विन मकालय, य०सी०प्रो बैंक बिल्डिंग, पार्लियमेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 जापानी सभरकों को भुगतान करने के लिए अनुबन्ध-3 में विए गए प्रपत्र ने बैंक आफ इण्डिया, टाकियों को भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र (ए/टी) "जारी करेगा। ए/पी की प्रतिया भारतीय दूतावास, टाकियों प्राधिकरण, भारत में आयतक का बैंक और दीसी०एम भुगतान, प्राधिक कार्य विभाग, वित्त मकालय को पृष्ठांकित करेगा।

6(2) भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र (ए/पी) प्राप्त होने पर बैंक आफ इण्डिया, टाकियों इस पावती की सूचना जापान सरकार, भारतीय दूतावास, टाकियों भारत में आयतक का बैंक और सीएमएस और ए की सूचना देते हुए सभरक का भी सूचना देगा। और भारतीय दूतावास, टाकियों को भजन का प्रबन्ध करेगा।

6(3) माल का पोल लक्षित करने के बाद विदेशी सभरक प्राप्त बैंकों का माध्यम से प्राधिकरण पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भगतान के लिए बैंक आफ इण्डिया, टाकियों को प्रमुखत करेगा। यदि दस्तावेज महा पाए गए हो बैंक आफ इण्डिया टाकियों द्वारा उल्लिखित धनराशि को विवेशी सभरक का इमक बैंकरा का माध्यम से रिहा नहीं।

6(4) प्राधिकरण पत्र में परामर्श के लिए और सभरक का भुगतान की अवधियता के लिए बैंक/आफ इण्डिया, टाकियों को चुकाए जान वाले बैंक वर्षे भारत में आयतक के सम्बद्ध बैंक द्वारा मामोल्य बैंक प्रणाली से भारत भारत सरकार के लेखे को प्रमावित किए जिन ही चुकाए जाएंगे।

खण्ड-7—रूपया जमा करने का उत्तरदायित्व

7(1) मूल विनियम पोत परिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक आफ इण्डिया, टाकियों द्वारा भारत में आयतक के मस्तिष्क बैंक को भेजे जाएंगे जो कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की एक शाखा होगी अथवा अनुबन्ध-3 में (ओ) उल्लिखित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा होगी। उम बैंक की वस्तावेजों के वे विनियम सेट केरल इस भाग की सुनिश्चय कर भेजे के बाद ही नाइर्मसधारी को भैने चाहिए कि जापानी सभरक को

चुकाई रही येन धनराशि के बराबर न्यूक्स और उस धनराशि पर विवेशी सभरक की बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से बास्तविष्ट रूपया जमा करने की तिथि तक ही नी अवधि पर पहले 30 दिनों में लिए ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और बैंक अवधि के लिए १५ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से शिसां लगा कर व्याज सार्वजनिक सूचना संख्या-५८ आईटीसी (पीएन)/२६ दिनांक १६-८-७६ के अनुसार सरनारी लेखे में जमा कर दिया गया है। व्याज होने दिन, प्रतिवृत्ति जिस दिन विवेशी सभरक की भुगतान किया जाता है, और जिस दिन मरकारी लेखे में रूपया जमा किया जाता है के लिए देय है। दूसिए मार्वजनिक सूचना संख्या-१०३ आईटीसी (पीएन)/२६, दिनांक १२-१०-७६ द्वारा प्रार्थोदित मार्वजनिक संख्या-७४ आईटीसी (पीएन)/२४, दिनांक ३१-५-७४ भुगतान की येन/य००८०० डालर/पौंड स्टर्लिंग धनराशि के बराबर रूपए की गणना करने के लिए धनराई जाने वाली विनियम वर मूल्य नियशक, आयात-नियरति की सार्वजनिक सूचना संख्या-८ आईटीसी (पीएन)/२६ दिनांक १७-१-७६ में निर्धारित मूल्य विनियम की मिश्रित वर हीमी या वह वर हाई औ चि भुगतान विनियमक आयात-नियरति की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्य विनियम नियशक परिपत्रों के माध्यम से मरकार द्वारा मम्य-मम्य पर अधिसूचित की जाए। इस सम्बन्ध में कोई भी पवित्रत जब और जैसे ही प्रावधान बागा, अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस आज का सुनिश्चय भरने का मस्तिष्क भारतीय बैंक ना उत्तरदायित्व होगा कि आयत वस्तावेज आयतकों को सोपन से पहले ही देय धनराशि सभरकी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। जिस लेखा शीर्ष में उपमूल रूपया जमा करना चाहिए, वह "के लियोजिट्स एण्ड एडवान्सिज ४४३ सिलिंग ट्रिपोजिट्स-ट्रिपीजिट्स फार परकेंजिंग एम्सट्रा एकान्ड परकेंजिंग प्रान्ट एण्ड फोम गवनमेंट आफ जापान फार १९७८-७९ (येन २ ९ विलियन प्रान्ट एड) होगा।

7(2) कपर उल्लिखित धनराशि या यो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, टीसी हजारी, दिल्ली, में सरकार की साथ में नकद जमा होनी चाहिए, या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसके उपसर्वी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुन्डीकर्ता) में प्राप्त एक "एड (ट्रिमाण्ड ड्राट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी शाखा दिल्ली-६ (हुन्डी शाहन और प्राप्तक) का सार्वजनिक सूचना संख्या १४४ आई टीसी (पीएन)/६८ दिनांक ३०८ १९६८, संख्या २३३ आईटीसी (पीएन)/६८ दिनांक २४-१०-१९६८, संख्या-१३२ आईटीसी (पीएन)/७१ दिनांक ५-१०-७१, संख्या ७४-आईटीसी (पीएन)/७४ दिनांक ३१-५-१९७४ और संख्या-१०३ आई टीसी (पीएन)/७६, दिनांक १२-१०-७६ में यथा निर्धारित स्करकारी लेखे में जमा करने के लिए धन परेण्य करना चाहिए।

7(3) सरकार द्वारा एसी मार्ग किए जाने के बाद मात्र विनी के भीतर मस्तिष्क भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित भरीके से बह अनियन्त्रित धनराशि सेवा खर्चों के नियमित भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा यारी जाए। बालान के विविध कालमों का भरत मम्य आयतकों/उनके बैंकों को इस भाग का सुनिश्चय कर भेजा जाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या-१०३ आईटीसी (पीएन)/७६, दिनांक १३-१०-७६ के साथ यारी जाने वाली सार्वजनिक सूचना संख्या १३२-आईटीसी (पीएन)/७१ दिनांक ५-१०-७१ में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेण्य और आवधिकारों (यदि कार्ड हो) के पूर्व औरे" में निस्पत्राव रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। याजाना चालान में निम्नलिखित औरे में निष्पत्राव रूप से प्रस्तुत भरने चाहिए --

(क) विस मन्त्रालय के प्राधिकार पत्र (भूगतान के लिए प्राधिकार पत्र) सम्पा और दिनाव

(ख) ये न मंत्रा की वह व्यवस्था जिसके गम्भीर में अपनाई गई परिवर्तन की दर के मात्र निष्पत्ति किए जाने हैं।

(ग) विद्युतीय सभरक का भूगतान करने की निवि

(घ) चुकाए गए द्वारा की व्यवस्था और वह व्यवधि जिसके लिए यह गिता गया है।

(ङ) जमा की गई गई कुल धनराशि

(जागनी सभरक को भूगतान की निवि से व्याज की गणना की जानी है और इसमें सरकारी लेवे य रुपया जमा करने की नीति भी शामिल है।)

उसके पश्चात् भी०८०४०० द्वारा जारी किए गए भूगतान में निए प्राधिकार पत्र का मर्दभ देने हुए और जीक लापा पोत परिवहन सम्बन्ध को सलमन करने व्यवस्था जमा रुपया जमा करने का गारुद देने हुए पंजीकृत डाक द्वारा भी०८०४०० का भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय बनाए चाहिए कि रुपय का निषेप भारतीय बैंक टोकियो से ग्राम्यांशी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत लापा वस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरापद रुप से किया जाना चाहिए और यह कि उसके तरफास बाद सी०८०४०० विस मन्त्रालय (आर्थिक भार्य विभाग) नई रिली को सूचित कर दिया जाएगा।

7(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रुपया निषेपों की धनराशि का पृष्ठाकल करना चाहिए और अपेक्षित 'एस प्रपल भारतीय रिजर्व बैंक शाफ बम्बई' को भेजना चाहिए।

7(5) बैंक गारन्टी और विस मन्त्रालय भी०८०४०० द्वारा जारी किए गए प्राधिकारपत्र के अनुसार आभारों को पूर्ण करने के बाव भारतीय सम्बद्ध बैंक, बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए सी०८०४०० से ग्रावेन बर मकान है। इस उद्देश्य के लिए आवेदनपत्र भनुबन्ध-7 में दिए गए प्रति में दिया जाना चाहिए।

#### प्राप्ति—8 विविध शब्द

##### 8(1) आयात लाइसेंस के उपस्थोग और रिपोर्ट

मानवत्र लोप जाने के बाद आयातक को पोत लदानों और उसके प्रधीन लिए गए भूगतानों के सम्बन्ध में श्रीर जो पोतमयान होन चाहिए है उसके विषय में पाँक मार्गिक रिपोर्ट भी०८०४०० का भेजनी चाहिए।

##### 8(2) सभरको की विवेश शब्द प्रधिसूचित करना

नाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात नाइसेंस की उन विशेष शब्दों में सभरको को अवश्यक करते जा समझौते का गायन करने में सभरको पर प्रभाव डाल सकती है।

##### 8(3) विवाद

यद्य समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और सभरको के बीच यह कोई विवाद उठेगा तो उसमें लिए भारत सरकार कोई उभरदायित्व नहीं लगेगा। बैंक शाफ इण्डिया टोकियो द्वारा भूगतान में पूर्व सभरको द्वारा पूरी की आव आला फैले भूगतान की जानों के बीच अनुबन्ध-1 में आयातक द्वारा साफ-साफ बना दी जाएगी। विवादों में निपटन की जानें तेक वाँ जानों में शामिल होनी चाहिए।

##### 8(4) विविध अनुबन्ध

आयात लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठ उडे होने वाले किसी भास्त्रे या वभी भास्त्रों से भवनश्वत या जापान में १९७८-७९ व लिए अनुबन्ध भवनश्वता के अवीन भभी आभारो का पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लिंगेश, अनुबन्धो वा ग्रावेणो का लाइसेंस-भारी को बुरस्त पालन करना हागा।

##### 8(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त बच्छों में लिंग की गई अन्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन बरते पर आयात नियाति (नियक्षण) अप्रियनियम के अधीन उचित नारेबाई की जाएगी।

##### 8(6) अनुबन्धों की सूची :

अनुबन्ध-1 पाल भाव देशों की सूची

अनुबन्ध-2 पाल पर्य वस्तुओं की सूची

अनुबन्ध-3 भूगतान के लिए प्राधिकरण पह जारी करने के लिए अवैदन

अनुबन्ध-4 भूगतान के लिए प्राधिकरण पह का प्राप्त्य

अनुबन्ध-5 अधिप्राप्ति के लिए विस्तृत विवादिति

अनुबन्ध-6 गारन्टी बाण्ड

अनुबन्ध-7 बैंक गारन्टी रिहा लगो के लिए आवेदनपत्र का आवैदन

अनुबन्ध ---1

(सहभं बच्छ-1 किंविका-1 (१))

पाल छोत देशों की सूची

क-भी०८०४००१०१०१० देश

पास्ट्रलिया

प्रास्ट्रिया

सेलियम

कनाडा

उत्तमाक

फिनलैंड

फोस

जर्मनी सर्बीय गणराज्य

यनान

आइसलैंड

आयरलैंड

इटली

जापान

लक्समबर्ग

नीदरलैंड

न्यूजीलैंड

नार्वे

स्वीडन

स्विटजरलैंड

तुर्की

यनान्डेप किंग्सम और मुक्त राज्य

(ख) विकासशील देश और सीवास

(ग-1) नान-भा०१०१०१०१०१० विकास शील देश

1 अफ्रीका, उत्तरी भवारा

मिश्र

भारत

टूर्नेशिया

2 अफ्रीका, दक्षिणी भवारा

अंग्रेजी

बोस्फ्राना

बहरहारी

मेंटरप	एस साल्पेडोर
झैप बर्बी झैप समूह	गुबाडेलोप
केल्ड्रीम घफीका गणराज्य ( 1 )	वाटेमाला
चाव	हस्ती
कमोरो झैप समूह	क्लोस्ट्रम
कागो दाहोमे गणराज्य ( 1 )	गमेका
भूमध्यवर्ती गिनी	माटिनिक
इयोपिया	मैकिसको
आम्बिया	नीदरलैण्डस एटिलीज
आता	निकागागुवा
गिनी	पनामा
आइवरी कोस्ट	सेन्ट पियरी और मिकेलोन
झीनिया	ट्रिनिडाड और टोबागो
देसीबे	सेट इष्टी ( शावा ) एन०आर००५०
लाइबरिया	( क ) सम्बन्धित राज्य ( 1 )
गालागासी गणराज्य	( घ ) आधित राज्य ( 2 )
मलाखी	4. दक्षिणी घमरीका :
माली	झर्जेटीना
मारिसिया	बोलिविया
भारिसम	बाबील
मुजम्बीक	विलेटी
नाइजेर	कोलम्बिया
पुतेगाली गिनी	पस्कलेड झैप समूह
रियूनियन	फ्रांसिसी गिनी
रोडेशिया	गुयाना
रवान्या	पाराग्वे
सेट हेलिना और डेप ( 2 )	पीलू
साप्टोटोम और ग्रिनाडप	सूरिनाम
सेनेगल	उरुग्वे
झेनिलिंग	5. मध्य पूर्वी एशिया :
सियरालिंगोब	बेहरीम
झोमासिया	इजराइल
झूडान	जोडेम
स्वातीलिंग	मेच्चनान
ईरा घाफर्स और इस्लाम	झोमन
टोतो	मिरियाई झरक गणराज्य
झूगाल्ला	झाइटेंड झरक अमिरान ( 3 )
संजानिया गणराज्य दंब	घमन झरक गणराज्य
झपर बोल्टा	घमन जनवादी झौ० आर० ( 4 )
जाइरे गणराज्य	6. दक्षिणी एशिया
आस्त्रिया	प्रकागामिस्तान
3. घफीका, उत्तरी और केन्द्रीय	जागाना देश
बेहप्स	भूटान
बारबाडोज	झर्मा
बेसाहिज	मालदिव
बरमुदा	मेपाल
कोस्टारिका	पाकिस्तान
झूडा	ओसंका
झोमिनिकन गणराज्य	

( 1 ) पहले स्वैंसी गिनी का प्रदेश, करनेवो पो० झैप सहित

( 2 ) निम्नलिखित झैपो सहित असेण्ट, ट्रिस्टम डा इन एक्सेसिविल्स, नाइटिंगेल गफ

( 3 ) झूड्य झैप समूह, झरका, जोवाहरे, झुराकामो, वाहा, ईस्ट, इस्टेसिट, मेस्ट, झारटिन ( दक्षिणी भाव )

( 1 ) मुड्य झैप एन्टिगुआ, झोमिनिका, पेनेज, सेल्किट्स ( सेल्किट्सीको ) मेंवित झूड्याला, सेल्सुसिया और सेट विसेन्ट ।

( 2 ) झूड्य झैप झोमेसरत, मेमान, तुक और काइकम और ग्रिटिम झरजिन झैप समूह ।

( 3 ) झूड्यान, क्लूप, फुजाइराह, राम झूल झीमाह गाइजाह और उम्बल झैवेस ।

( 4 ) प्रख और विभिन्न मान्यता और घरीरान सहित ।

७ पूर्व पूर्वी गणिता  
बलदी  
हास्याभ  
खेमर गणितन्त्र  
फोनिया गणितन्त्र<sup>१</sup>  
लांगोम  
मवाधा  
मरोणिया  
फिलिपान  
सिंगापुर  
ताहवान  
थाईलैण्ड  
तिमौर  
वियतनाम गणितन्त्र<sup>२</sup>  
वियतनाम जनवादी गणितन्त्र<sup>३</sup>

८ ओमिनिया

8 श्रोमिनिया

नोकटीग ममूह  
 किरी  
 गिल्बट और इ राइग द्वीप  
 कांसिना पालिनिया (5)  
 नोर  
 न्यकालेडीनिया  
 न्यु हेलिमेस (क्रि आ के)  
 लियू  
 पैटिफिक द्वीप ममूह (मंगुक्त राज्य) (6)  
 पायुचा न्यू गिरी  
 मोलोमत द्वीप ममूह (कि)  
 टोगो  
 वालिस और फ़्रुन्ता  
 पश्चिमी मसीओ

१०८

साहप्रस  
प्रिवेल्टर  
प्रीक  
मार्क्टा एम  
प्रद  
टकी  
यूगोस्लाविया  
(अ) २) धारा १०४० वी० के महस्य पा सवधित देण  
यूक्रेनिया  
बोस्निया  
निष्पात्र ग्राहक गणराज्य  
गान्धीन  
नाईजीरिया  
एक्यूडोर  
वैन्क्रान्टा  
ईरान  
ईरास  
कुवैत  
कुवात  
सऊदी अरब  
आबू धाबी  
इम्फोनेशिया

(५) सोमायर्टी द्वीप समूह (नाशिकी महिन) को सामिल करते हुए प्रास्ट्रुल द्वीप समूह द्वारा बोट, जाम्बिकार सुप ब्रीन यांकेसस द्वीप समूह ।

(६) ऐमिकिक द्वीप समूह का द्वारा प्रदेश : कारोलीन द्वीप समूह, मार्वेल द्वीप समूह और बेरिन द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

प्राचीन भाषा 2

पाठ्य पत्र सूची

- १ राज्य
- २ विशेष इस्पात और मिशनातु इस्पात संवित इस्पात
- ३ ट्रॉको और ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए संचाटक, संयोजन और पुर्जे।
- ४ रसायन
- ५ भारत-जापान समुक्त उद्यम के लिए फालतू पुर्जे, सब्कटक और कच्चा माल
- ६ विज्ञिनी के हस्तों के लिए संचाटक, संयोजन और फालतू पुर्जे।
- ७ भर्तीनगी संचाटक, संयोजन, फालतू पुर्जे और कच्चा माल।
- ८ भारत के ग्राम्य लघु उद्योग नियम के लिए मणीनगी और उपस्कर।
- ९ व्यापारी हाई आफ और डिवेलोपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मणीनगी और उपस्कर।
- १० उच्चक और ऐसी धन्य भड़े जिन पर आपस में सहमति हो।

परमार्थ ३

बुगतान के लिए शाखिकार्यक्रम जारी करने के लिए शार्चना-प्रक्रम सेवा में।

महायदा लेखा एवं लेखा परीक्षा नियमक  
वित्त मंत्रालय,  
भार्यक कार्य विभाग,  
मु०सी०प्र०० बैंक विभाग,  
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-१ 110001

विषय -- 1978-79 के लिए 29 विनियत की जापानी प्रनृशान महायता के प्रत्यर्थी जापान से आयात।

लेपर उत्तराखण्ड ग्राम्यानन्द महायाता के अन्तर्गत आपान से .  
के ग्राम्यानन्द के संबंध में हम आपको निम्नलिखित व्यौरे भेजते हैं जिससे  
कि ग्राम्य सम्बद्ध संभरक के पक्ष में बैंक और इंडिया, टोकियो को प्राप्तिकार  
पूर्ण जारी कर सके —

(क) भारतीय आपातक का नाम और पता

(ब) प्रायास लाइसेंस की सख्ति, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक बैंध रहे।

(म) प्राप्ति के सरीके—क्या यह सीधे क्या या योपचारिक बुली प्रत्यरूपीय निविदा पर आधारित हैं। इसके भासले में यदि कोई हो तो कारण सहित यह संकेतित होना आहिए कि व्यवहार मविदा का तिर्यक उत्तरकृत न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(b) माल का संक्षिप्त विवरण।

(क) माल का उद्गम होगा।

(b) संविधा का कुल भाग और भाषा भल्य (येन मे)

(क) भारतीय स्पष्ट संभवतान के योग्य भारतीय प्रवेश में कमीता का धर्मांश (ये न में) यदि काहि हो।

(अ) कुल लागत और भाड़ा मूल्य (बेत में) जिसके लिए प्राप्तिकरण-पत्र की घोषणाक्रता है।

(म) सभस्को के साथ सविदा का नाम और दिनांक।

(अ) वंशरक का नाम और पवा प्रौर पात्रता व भगवत् (से प्रत्येक में) मन्त्रन किया जाए।

(ब) भूगतान शर्तें और सम्भावित निषिद्धि जिनके सावधाने प्रत्यर्गण भूगतान बरना है।

(च) सुर्वर्गी को पूर्ण करने की यम्भावित निषिद्धि।

(द) बैंक ग्रॉफ इण्डिया टोकियो को भूगतान के समय प्रत्यक्ष किया जाने वाले दस्तावेज़ (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपातार दर्शन हुए)

(४) पोतलवान अनुदेश (यथा पोतलन्त्रण/प्राणिक पोतलवान अनुदेश के प्रवचन नहीं, दर्शाएँ)

(५) भारत में आयातक बैंक का नाम और पवा।

(६) किस प्रवधि नक्क वैष्ण द्वारा दर्शने हुए बैंक गारटी की संख्या, विनांक एवं मूल्य।

भवदीय

## अनुबंध-४

संख्या

भारत सरकार

## वित्त मन्त्रालय

## प्राधिक वर्गमें विभाग

नई दिल्ली

दिनांक

संखा में

बैंक ग्रॉफ इण्डिया  
टोकियो शाका  
टोकियो (जापान)

विषय -- २-९ विविधन के लिए जापानी अनुदान सहायता के प्रधीन आयात-भूगतान के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

१. आपके बैंक के साथ १-३-७५ का विषय यथा संबंधित को शर्तों के प्रत्युत्तर प्राप्तको एन्ड्रिया यथा सत्त्वन ग्रॉफ (जो परिणिष्ट में दर्शाएँ गए हैं) के अनुसार सर्वेत्यों

के नाम में '..... येन .. की शतराणि के भूगतान के लिए प्राप्तिकृत किया जाना है।

२. कृपया सूचना दें यदि प्रत्येक सूचना-पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजदर्नायां टोकियो और इस मन्त्रालय को पूँजीकृत की जाए।

३. भूगतान के लिए प्राधिकार पत्र की जर्ती के अनुसार भूगतान [परिणिष्ट में वधु संवेदित लदान दस्तावेजों के धाधार पर] किया जाएगा।

४. आयातक द्वारा यथा को यदि काई हो तो दस्तावेज़ के लिए यथा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़ों भवित भावे भी मीठे ही आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

५. ऐसे ही जापानी वस्त्रको द्वारा प्रत्यक्ष किए गए लदान सूचनाएँ भेजा धाधार पर यथा कोई भी भूगतान किया जाता है तो उसकी सूचना निर्धारित प्रत्यक्ष में वस्त्रालय और आयातक के बैंक का भेजी जानी चाहिए।

६. इस मन्त्रालय की विशेष अनुमति के बिना भूगतान के लिए प्राधिकार-पत्र के लिए काई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

७. मठ भूगतान के लिए प्राधिकार-पत्र तक वधु रहेगा।

भवदीय  
लेखा अधिकारी  
प्रति निम्ननिषिद्धन का प्रेषित ---

१. प्रायोगिक

दिनांक

का उत्तर पद भव्या

के सदृश्व में

२. आयातक का वैक्षणिक उनमें निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक ग्रॉफ इण्डिया, टोकियो शाका से दस्तावेज़ प्राप्त करने पर विवेशी संभरको को मेन के ब्राष्टर रूपया जमा करने की व्यवस्था बरे। संभरको को चुकाई गई धरमराणि के ब्राष्टर रूपया की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या-४ प्राई टी सी (पी एन)/७६ दिनांक १-७-७६ वा अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार जापानी संभरको को भूगतान करने की विषि को यथा प्रतिविनियोगी की मिश्रित दर पर की जाएगी। संभरक को भूगतान करने की विषि में भरकार के लेखे में तुल्य रूपया जमा करने की विषि तक की व्यवधि के लिए सार्वजनिक सूचना मं० ४६-प्राई टी सी (पी एन)/७६ दिनांक १६-६-७६ के अनुसार पहले ३० विनों के लिए ९ प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे प्रधिक की गणना की गई व्यवधि के लिए १५ प्रतिशत की दर से स्वामी भी संभरकी लेखे में जमा करना होगा। स्वामी दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा प्राप्तिकृत वह विषि जिसको जापानी संभरक को भूगतान किया जाता है। और वह विषि भी जिसको संभरकी लेखे में रूपया निषेप किया जाता है। (इस दर से यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुल्य उसकी सूचना वी जाएगी)। यह मुनिषिद्धन कर देना चाहिए कि आयातक को सीमा शूल निकासी के लिए प्रायात दस्तावेजों का मूल में रिए जाने से पूर्व यह धनराणि प्रमा की जानी है।

ये धनराणियां या तो विज्ञवं बैंक ग्रॉफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ग्रॉफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करने वाली हैं या स्टेट बैंक ग्रॉफ इण्डिया की किम, राजा या इसकी सूचनाएँ नेस्पासों या किमी भी गण्ड्यांकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त का गई स्टेट बैंक ग्रॉफ इण्डिया, तीस हजारी शासा विल्सन-६

(प्रादेशिक और आदाना) के नाम में और उसको द्वेष दर्शनी हुन्ही के माध्यम से जमीनी चाहिए। इस सबधि में आपके द्वारा सार्वजनिक सूचना मं० २३-प्राई टी सी (पी एन)/६८ दिनांक २४-१०-१९६८, यम्भा १३२-प्राई टी सी (पी एन)/७१ दिनांक ५-१०-७१, यम्भा ७५-प्राई टी सी (पी एन)/७४ दिनांक ११-५-७४ और मूल्य १०३-प्राई टी सी (पी एन)/७६ दिनांक १३-१०-७६ की शर्तों की द्वारा दिलाया जाता है। नेवा शीर्ष विसमें धनराणि जमा की जाएगी वह "क डिपोजिटस एण्ड एडवानस-४१३ विशिल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फॉर पर्सेंसिस एडमेंट्स एडवेजिस आन्ड एन्ड फ्राम दि एवेन्युमेंट ग्रॉफ जापान फॉर १९७८-७९ (यैन २-५ विविधन प्राप्ति एन्ड एन्ड)"

जिस मामलों में तुल्य रूपया विज्ञवं बैंक ग्रॉफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ग्रॉफ इण्डिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना मं० १३२-प्राई टी सी (पी एन)/७१ दिनांक ५-१०-७१ से अनुसार नवद जमा किया जाता है उसमें जापान की मूल रूपया में एक प्रतिविनियोगी विज्ञवं बैंक ग्रॉफ इण्डिया टोकियो जापान से प्राप्त सूचना डिप्पली का पूर्णविवरण यैन द्वारा व्यवधि वह सहित उनके द्वारा निम्ननिषिद्धन को पर भेजी जाएगी —

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियमक,  
विन संवालय (आर्थिक कार्य विभाग),  
पहाड़ी मंजिल, यू सी आईक बिल्डिंग,  
समद मार्ग, नई लिलो ।

जिस मामले में तुल्य रूपया ऊपर संकेतित मार्गेजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हड्डी द्वारा प्रेपित करना है उगकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर येजी जानी चाहिए । सर्वे मामलों में व्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अधिगति के लिए शात्र की गणना की गई है उसके साथ जमा किए गए तुल्य रूपया का पूरा ब्यौग इस विभाग की भेजना चाहिए ।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के बच्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंक अवै और बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो ब्रांच के अन्य बच्चे इण्डियन बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो शाक्का द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे ।

4 भारतीय बूताकास टोकियो ।

5. अवर संविधि (टी सी एम) शाक्का विह संवालय आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।

लेखा अधिकारी

प्रत्यन्धन्ध-5

जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत पर्यवर्तुलों की अधिगति के लिए भागदर्शन

## 1. प्रस्तावना

जापान की सरकार द्वारा बड़ाई गई 2.9 खेलियन येन की अनुदान सहायता रकमों का उपयोग इस मार्गवर्तीन में दी गई अधिगति की कियाविधियों के अनुसार पात्र ज्ञात देशों के बीच क्षमता और किसी भेदभाव के बिना पर्यवर्तुलों की अधिगति और उनके लिए अनुचितिक सेवाओं के लिए उचित विचार के साथ किया जाएगा ।

## 2. अधिगति की व्यवस्था

अनुदान सहायता के अन्तर्गत सूचीबद्ध पर्यवर्तुलों की अधिगति के लिए निम्नलिखित कियाविधियां लागू होंगी ।

- (1) श्रीपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा देना
- (2) श्रीपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय संविदा देना
- (3) श्रीपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिगति
- (4) सीधी खरीद

(क) सरकार और/या सरकारी एजेन्सी द्वारा अधिगति के मामले में श्रीपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा या श्रीपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू होगी ।

(ख) गैर-सरकारी अधिगति के मामले में उपर्युक्त उल्लिखित कोई भी कियाविधि लागू हो सकती है ।

(ग) ऐसिं इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में प्रतीपत्तारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिगति या सीधी खरीद के माध्यम से अधिगति कर स्वीकार करना सम्भव है ।

- (1) संविदा की मुद्रा की गतों के अनुमान जहां प्रस्तावित संविदा की धनराशि 300,000,000 येन, 1,500,000 यू एम डालर या 800,000 पौण्ड स्टर्लिंग से अधिक नहीं है ।
- (2) जहां अहक संभगों की संख्या सीमित है ।
- (3) जिस मामले में किसी विशेष विशिष्टकरण, ट्रैड नाम या पदनाम के सदर्चन द्वारा किसी पर्यवर्तुलों की खरीद उपस्कर के अन्तर-परिवर्तन या मानकीकरण, या विशेष डिजाइन की आवश्यकताओं के कारण का भुतिश्चय करने के लिए आवश्यक हो ।

(4) जिस मामले में उपर्युक्त मामला (1), (2) और (3) (पर्याप्त श्रापती अधिगति के मामले में) से भिन्न कारण द्वारा या या कियाविधि (1) या कियाविधि (2) लागू हो ।

(घ) ऊपर उल्लिखित किसी भी मामले में आयातक इस खण्ड के 1-3 तक में निर्धारित अधिगति के अनुमान अधिगति की पात्रता से सम्बद्ध कर्तव्य को पुष्टि प्राप्त करेगा ।

## 3. संविदा की गतें

इस प्रवृत्ति सहायता के अन्तर्गत विवाह वात को जाने वालों कोई भी संविदा निम्नलिखित गतें पूरी करेगा :

### (1) पुण्य वस्तुओं की गतें

केवल, संप्रवृत्ति सहायता का उपयोग पात्र ज्ञात देशों में उत्पादित सूचीबद्ध पर्यवर्तुलों के लिए बच्चों का वित्त बात करने के लिए सीमित है इस लिए संविदा विषयक मद पात्र ज्ञात देश में उत्पादित सूचीबद्ध पर्यवर्तुलों की श्रेष्ठ दी जाएंगी । यदि पात्र ज्ञात देशों में आयातित भाग निम्नलिखित कार्यक्रम से तीस प्रतिशत (30%) से कम होगा तो सूचीबद्ध पर्यवर्तुलों के वित्त की जाएंगी मते हो वे संविदा को मदों में सूचीबद्ध पर्यवर्तुलों के प्राप्ति के रूप में गैर-पात्र ज्ञात देशों में आयातित भाग के रूप में शामिल की जाएंगी । ऊपर उल्लिखित कार्यक्रम ।—

आयातित कीमत + आयात शुल्क

संभरक की जहज पर्यान्त निशुल्क कीमत × 100

### (2) संभरक की गतें

संभरक पात्र ज्ञात देशों का राशिक होगा, या पात्र ज्ञात देशों में पंजीकृत न्यायिक व्यक्ति होगा ।

### (3) आयातक की गतें

जगत्का सेवा या, उसमें भाग्यता प्राप्त मार्गीय सम्बद्धों द्वारा किन्हीं भी पर्यवर्तुलों की अधिगति इस रूप के अन्तर्गत पात्र नहीं होगी ।

### (4) मुद्रा का मूल्य वर्ग

मविदा कमश १०० येन (वाई 1.50) एक सेन्ट (सी 1.00) या एक पैसी (धी० 1.00) से कम किसी भिन्न के विना ही जापानी येन, यूनाइटेड स्टेट डालर या स्टर्लिंग पौण्ड में निर्धारित की जाएंगी और वेत होगी ।

### (5) संविदा का मानक प्रपत्र

(क) इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत वित्तकान की जाने वाली संविदा में निम्नलिखित मदे शामिल की जाएंगी :

(1) संभरक और आयातक का नाम और राशिकता

(2) संविदा की संख्या और विनांक

(3) पर्यवर्तुलों का नाम और मूल स्थान

(4) संविदा का मूल्य और मात्रा

(5) अवश्यकीय गतें

(6) भुगतान और पोनकान अनुभूति

(7) अन्य भाग्यता विनियमन

(ख) वोनों पाटियों द्वारा विधिवत् इस्तावारित संविदा या विशेष संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टि घ्रावेश द्वारा समर्थित विदेशी संभरक को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए विक्रय आदेश, या उनकी कोटी प्रतियों भी स्वीकार्य हैं ।

(ग) पात्रता का निम्नलिखित विवरण संभरक द्वारा प्रत्येक संविदा में शामिल किया जाएगा :

“मैं (हम) एतद्वाग उल्लेख करना हूँ/करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी ..... (पात्र भौत देश) में पंजीकृत है।”

(6) भूगतान

प्रत्येक भूगतान अनुदान महायना की हस्ताक्षर करने की तारीख पर्याप्त 17 मार्च, 1979 को प्रथम हस्ताक्षर किया जाएगा।

पिछात के रूप में, संभरक को पोतलदान की पूरी धनराशि अपरिवर्तमीय सांख्यक के अन्तर्गत संबंधित पौत्र परिवहन दस्तावेजों के बैक और इण्डिया टोकियो को प्रस्तुत करने के प्रत्येक समय पर अवाक की जाएगी।

4. अन्तर्राष्ट्रीय संविदा का टेलर बैना

जब अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू की जाए तब अन्य नियमों के साथ निम्नसिद्धि नियमों के अनुसार अधिकारित की जाएगी :

(1) विशेषन बैकर

श्रीपत्रारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदाकरण के अधीन सभी संविदामों में बोली मांगने के लिए भारत में सामान्य रूप से प्रकाशित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में निविदा की जाएगी।

(2) बोलियों के मांगने और उन्हें प्रस्तुत करने के बीच का समय का अन्तराल

बोलने तैयार करने के लिए अनुमति समय ज्ञात बड़ी सीमा तक संविदा के महत्व और पेचीबगी के ऊपर निर्भर करेगा। सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम में कम 30 दिन स्वीकृत किए जाने चाहिए। किन्तु अनुमित समय प्रत्येक संविदा में संबंधित हालातों द्वारा नियकित किया जाना चाहिए।

(3) बोली बोलने की क्रियाविधि

बोलियों की अनियम पावती के लिए श्री और बोली बोलने के लिए श्री, समय श्री और स्पात की बोली आमंत्रण में शोधित किया जाना चाहिए और सभी बोलियों निर्धारित भवय पर छुले आम बोलनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना बोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी बैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि और से पहली जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

(4) बोली बाण्ड या गारंटीयां

बोली करने के मामले में, बोली बाण्ड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएँ हैं, किन्तु इनको इतना ऊंचे स्तर पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए जिससे उपयुक्त बोलीकार नियमानुसार होने चाहिए।

बोली बाण्ड या गारंटियां बोली छुल जाने के बाद यथार्थी असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए।

(5) मापदण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह वर्णन जाना चाहिए कि जापान और अमेरिका मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पर्याप्त वस्तुएँ जो मापदण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर निया जाएगा।

(6) ब्राण्ड नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतु पुँजों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीरण की एक छिकी की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण

निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें केवल ब्राण्ड नाम, मूँची मंड्या या विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्वाचित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पी पर्याप्त सुनुग्रहों के प्रमाणों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती-जुलती है और कम में कम उस विशिष्टिकरण के बराबर निष्पादन प्रोग्राम उनमें हैं।

(7) गारंटी और निष्पादन बाण्ड

यदि आवश्यक हो तो बोली संबंधी दस्तावेजों में गारंटी के लिए जमानत जमानत के रूप में कोई प्रपत्र होना चाहिए। यह जमानत या तो बैक गारंटी द्वारा या निष्पादन बाण्ड द्वारा दी जा सकती है।

(8) निर्धारित क्षमता

यदि आवश्यक हो तो जब कभी सुपुर्वी में फालतु चुंब होता हो, राजस्व की हानि हो या आवासक के लिए अन्य लाभ की हानि हो तो बोली संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित क्षमता वाक्यांश जोड़े जाने चाहिए।

(9) विवरण स्थितियां (फोर्म मेज्यूर)

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस मंबंध में बाक्यांग होने चाहिए कि संविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने वायिल्टों को न पूरा करना उस हालत में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवर स्थितियों (फोर्म मेज्यूर) के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा की जानी है)।

(10) शगड़ों का निपटान

शगड़ों के निपटान से मंबंधित व्यवस्थाएँ संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह बांछानीय है कि व्यवस्थाएँ अन्तर्राष्ट्रीय वायिल्ट समझन द्वारा बनाए गए “समसीते और मध्यस्थ-नियम के नियमों” या भारतीय एवं समुद्रपार के संभरक दोनों को स्वीकार्य होने वाली व्यवस्थाओं पर आधारित होते चाहिए।

(11) मूल्यांकन

अनुशंसा-6

[संदर्भ बाण्ड-5 कडिका-5 (2)]

गारंटी बाण्ड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

जारी किए गए आवास लाइसेंस संख्या ..... दिनांक ..... के आधार पर ..... द्वारा .....  
.....

(जिसे बाद में आवास कहा गया है)

के आवास के लिए भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें बाद में “सरकार” कहा गया है) के हेतु येन/यूएस डालर और पौण्ड स्टर्लिंग में भूगतान करने की व्यवस्था करते के लिए संहत होने हुए हैं .....  
आवासक बैक की प्रार्थना पर उपर्युक्त अनुदान महायना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धिष्ट रीति से और उचित नेतृत्व शीर्ष में सरकारी लेखे में जमा करते के लिए भूगतानों की सूचना पावती की तिथि से वह दिनों के भीतर बैक और इण्डिया, टोकियो द्वारा व्यवहार की गई धनराशि को मुख्य नियंत्रक, आवास-नियाति द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 8 आई टी सी (पी एन)/76—, दिनांक 17-1-76 में निहित अनुमार प्रथम सार्वजनिक सूचनाएँ/जी परिवर्त में समय-समय पर व्याधिसूचित के अनुमार परिवर्तित मिश्रित दर के क्रियाव द्वारा इस धनराशि में समुद्रपार संभरक की भूगतान होने की नियम से सरकारी खाते में समतुल्य रूपया जमा होने की तिथि तक की व्याधि पर प्रथम 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज जोड़ कर

और इससे अधिक गणना को गई अवधि के लिए 15% वार्षिक दर से व्याज को जोड़ कर धनराशि जमा करने की अवधि करने का एन्ड्रूड्यूरा व्यवहर देने हैं। ऐक आफ शॉण्ड्या, टार्कियो से प्राचीन आयात प्रतेकों का परकार्य सेट आयातक को लागे लौटाया जाएगा जब कि उत्तरुक अरेक्षित व्यया जमा कर दिया गया हो।

2. हम दि..... बैंक, समय-नमय पर ऐसे स्थान और ऐसी रीति से जो सरकार निविष्ट करे, आयातक द्वारा सरकार को देय अवधि चुकाने योग्य किसी धनराशि को जो..... रुपए से अधिक न हो या निपिलम समय के भीतर आयातक द्वारा देय या चुकाने योग्य धनराशि के किसी भाग को और समुद्र पार समरकों को भुगतान करने की तिथि से 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक व्याज और इससे अधिक गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज को दर से व्याज को न चुकाने में आयातक की सुटी होने पर स्वयं क्षतिरूपि करने का और सरकार को क्षतिरूपि के व्याख्यात से मुक्त रखने का भी व्यवहर देने हैं। उक्त भुगतान में आयातक द्वारा या उसको तरफ से हमारे..... ऐक द्वारा सरकार को देय धनराशि के मन्त्रव्य से किसी प्रकार का त्रुटी सरकार का निर्णय अनिम होगा और हमारे बैंक पर लागू होगा।

3. हम..... बैंक, आगे इस बात पर महमत है कि सविदा के अन्तर्गत आयातों के मूल्य में या जा साल लुडाना आकाएँ उसके मूल्य में उपगुक्त वैरा एक में उलिविन मुद्रा विनियम के मिथिम दर में परिवर्तन होने को स्थिति में, जब से परिवर्तन हुआ है इस परिवर्तन के अनुवान में इस बैंक गारंटी आड को धनराशि का समाप्तिजित कर निया जाएगा।

4. हम..... बैंक, आगे सहमत है कि इसके अन्तर्गत यह गारंटी उक्त करार/संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक इसके अन्तर्गत सरकार को देय सब बकाया पूर्ण रूपें नहीं चुकाए जाते और इस गारंटी को हैमियत से दावों को पूर्ण नहीं कर दिया गया हो या वे अवा नहीं कर दिए गए हो।

5. इस गारंटी पर आयातक या दि..... बैंक, के विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने में प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारंटी का प्रभावित किए जिन आयातक पर लागू होने वाय किसी भी अधिकार को किसी समय या समय-नमय के लिए स्थगित करे और पूर्वकता मार्गों के सदस्यों में या आधोतक को दिए जा रहे समय के कारण या सरकार की ओर से किसी अन्य स्थान, निर्णय या कूट या सरकार द्वारा आयातक पर किसी अन्यथा या कानून के अन्तर्गत प्रतिरूपियों से सम्बन्धित कोई भी मासला या वस्तु जो इस परन्तुके लिए दि..... बैंक को इसके वायिस्को से नुक्त करने के लिए प्रभाव छाने, सरकार द्वारा इन मासलों में किसी प्रकार को स्वतन्त्रता ला दिये जाने से इस गारंटी के अन्तर्गत दि..... बैंक, अपने वायिस्को से मुक्त नहीं होगा।

6. हम..... बैंक अन्त में यह व्यवहर देते हैं कि सरकार की सिविल पूर्ण अनुमति के बिना इस गारंटी को इसकी चाल अवधि के दौरान रह नहीं करें।

7. इस बाड/गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व..... रुपए (व्याज और कमीशन प्रभाव जिसकी आशा गारंटी की धनराशि के एक प्रतिशत से अधिक होने की नहीं है) तक प्रतिविधित है और वह गारंटी दिनांक..... तक प्रभाव जब तक इस तिथि से 6 महीनों के भीतर इस गारंटी के अन्तर्गत शब्दे पूर्ण नहीं कर दिए जाते हैं और जब तक प्रभाव 6 महीनों के भीतर इन दावों द्वारा लागू करने के लिए आवेदन द्वारा आयातक नहीं की जाती, और तब लागू रहेगी। इसके बाद अवृत्त दिनांक..... तक इस बाड/गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सब अधिकारों से छुटकारा और कार्य नुक्त मिल जाएगा।

दिनांक..... 1979  
कृते..... बैंक  
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनका मार से थी.....

(ताम तथा पवनाम)

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

\*\*जिस तिथि तक साथ-पत्र का वैध रखने की आवश्यकता होनी है उस तिथि में एक महीना जोड़कर यह तिथि गिरा जाएगा।

टिप्पणी :—जिस स्टाम्प पेपर पर यह गारंटी कार्यान्वयन की जाती है उसके मूल्य का निर्णय भारतीय स्टाम्प अधिनियम कीधारा 31 के प्रनग्न स्टाम्प समाहर्ता द्वारा किया जाता है।

अनुशन्ध-7

[खण्ड-7, फंडिका-7 (5)]

बैंक गारंटी की रिहाई के लिए आवेदन-पत्र का प्राप्त्य संदर्भ में,

सहायता नेका तथा लेक्षा परीक्षा नियवक,  
वित्त मंत्रालय वार्षिक कार्य विभाग  
यू सी बैंक विलिंग,  
पार्लियामेंट स्ट्रीट,  
नई विल्ली-110001

महोदय,

हम..... रुपये के लिए बैंक गारंटी मंज्या विनाक..... के अन्तर्गत अपने दायित्व के भूगतान में हमारे द्वारा जमा किए गए रुपये की विस्तृत मूकता नीचे इस आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि बैंक गारंटी रिहा को जाए और हमें लौटाई जाए।—

1. जिसकी ओर से बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी उस आयातक/लाइसेंसवारी का नाम और पूरा पता

2. आयात लाइसेंस का मंज्या, दिनांक, मूल्य उसके प्रधीन आयात की लिए अनुमेय किए गए उपस्कर और/या पण्य वस्त्रों का विवरण।

3. विभ मंत्रालय से प्राप्त किए गए प्राविकरण के ब्यौरे (प्रत्येक प्राधिकरण पत्र के लिए प्रत्यक्ष में व्यौरा दिया जाना है।

(क) पत्र मंज्या और दिनांक

(ख) प्राधिकरण की धनराशि

(ग) 2.9 विनियम येत की जापान अनुवान सहायता

4. आयात के और जमा किए गए रुपये के ब्यौरे (प्रत्येक प्राधिकरण के लिए अलग से व्यौरा दिया जाना है।—

(क) येन/यू एन डालर/पौरो में बोक की धनराशि (कुल)

(ख) जमा किए गए रुपए की धनराशि

(ग) संबंधित चालान मंज्या और दिनांक ग्राम राजकोष/बैंक का नाम

(घ) यदि रुपए दर्जी द्वारा जमा किए गए हों तो वर्णनी दुण्डी की संज्ञा और दिनांक और जिस पत्र के साथ दर्जी दुण्डी बैंक आफ इडिया, दिल्ली का भेजी थी उसकी मंज्या और दिनांक।

5. प्रत्येक प्राधिकरण में उपयोग की गई और बिना उपयोग की गई शेष धनराशि (येन/यू एन स्ट्रिंग/पौर)

2 हम प्रमाणित करते हैं कि —

(1) \*वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए प्राधिकरण (एा) में अन्तर्भुक्त येत की शेष धनराशि उपयोग नहीं की गई/उत्तीर्ण नहीं की जाएगी ।

(2) विद्यायाधीन बैंक गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व विधिवत पूर्ण हो गया है ।

3 हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि बैंक आफ इंडिया, दोकियो का ब्याज और बैंक प्रभार इस सौदे से संबंधित समुद्रपार सम्परकों के देकरों, के भाड़े बैंक आफ इंडिया, दोकियो को हमारे द्वारा भेज किए गए हैं ।

4 अनुरोध है कि बैंक गारंटी रिहा की जाए और निरन्तर करने के लिए हमें लोटा भी जाए ।

मन्त्रीय,

[बैंक के लिए और बैंक की ओर से प्राधिकरण अधिकारी]

\*जो भी लागू हो ।

**MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION**

(Department of Commerce)

**PUBLIC NOTICE NO 49-ITC(PN)/79**

**IMPORT TRADE CONTROL**

New Delhi, the 24th September, 1979

**Subject :** Terms and conditions governing the issuance of import licences for public and Private sector imports under the Japanese Grant Aid for 1978-79 extended by the Government of Japan.

**No. IPC/39/18/78.**—The terms and conditions governing the issuance of import licences for Public and Private Sector imports under the Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion (2,900,036,000) extended by the Government of Japan for 1978-79 as given in Appendices I and II respectively to this Public Notice are notified for information.

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports and Exports

**APPENDIX I TO DEPARTMENT OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 49-ITC (PN)/79 DATED 24-9-1979 LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF PUBLIC SECTOR IMPORTS UNDER THE JAPANESE GRANT AID OF YEN 2.9 BILLION ( 2,900,036,000) FOR 1978-79 EXTENDED BY THE GOVT. OF JAPAN**

Section I—General Conditions :

I (i) The Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion extended by the Government of Japan is untied in favour of OECF and developing countries. Accordingly the commodities and services, incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. However, if commodities imported under the licence contain components originating from a non-eligible source country or countries, it should be ensured by the importer, while negotiating a supply contract, that the total c.i.f. cost, including import duties, of such components imported into the country of the supply contract is less than 30 per cent of the f.o.b. value of the supply contract. In such a case, a certificate to this effect should be obtained from suppliers and attached to the supply contract. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I (ii) The licence will bear the superscription "Yen 2.9 billion Japanese Grant Aid for 1978-79". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment

towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (TCM Section) in the matter.

I(v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary, Department of Economic Affairs (TCM Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (Within 4 months from the date of issue of the import licence. "Firm Orders" mean, purchase orders placed by the Indian licensee on the Overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, TCM Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1 (v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (TCM Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 30-6-1981.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract

II(i) (a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) For individual imports not exceeding Yen 300 million or US \$ 1,500,000 or £ 800,000 in value (exclusive of Indian agents commission) the licensee is free to effect purchases directly from the suppliers without recourse to international tender enquiries from the countries listed in Annexure-I.

II(iii) Where, however the supply contracts exceeds the value limit prescribed in II (ii) above (exclusive of Indian Agents commission), the following procedure for procurement should be rigidly followed—

(a) Formal Open International Tendering

(b) Formal, elective International Tendering

(c) Informal International Competitive Procurement

II(iv) Any reference to International Tendering or International Procurement will mean tendering or Procurement, as the case may be from the eligible source countries

The above procedure may be relaxed in favour of Informal Competitive procurement or Direct Purchases where

1. a number of qualified suppliers exist in one particular country or in a limited number of countries;
2. purchase of a commodity by reference to a particular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the interchangeability or standardisation of equipment or because of special design requirements;
3. where purchases are in the category of emergency procurement.

The licensee is therefore advised that in case where the procedure at (a) and (b) of Para II(iii) above cannot be taken recourse to a reference to the Department of Economic Affairs shall have to be made who will give necessary approval on merits of each case.

II(v) Where Formal Open International Tendering is resorted to the following points should be borne in mind :—

- (a) Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.
- (b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be so high as to discourage suitable bidders.
- (c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(vi) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

#### II(vii) Eligibility of Supplier

The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

#### Section III

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 17th March, 1979 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 2.9 billion for 1978-79 "and will be subject to the approval of the Government of India."

III(ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorisation to pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1978-79.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where Suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importers require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

III(v) A certificate in the form indicated below :—

"I (We) hereby state that my (our) Company has been registered in \_\_\_\_\_ (eligible source country) and is governed by nationals of the eligible source countries, or juridical persons registered and incorporated in the eligible source countries."

III(vi) Where supply contract is based on formal Open International Tendering or Formal Selective International Tendering a certificate to the following effect should be furnished :—

- (i) Name of the Newspaper(s) in which the bid specifications was published;
- (ii) Name of parties who quoted against the tender enquiry;
- (iii) the reason for selecting a particular offer indicating whether it is the lowest technically suitable bid.

NOTE:—For detailed procedure for procurement of commodities and finalisation of supply contract see Annexure

#### Section IV—Contract Approval by Government of India

IV(i) As soon as the orders are finalised, the licensee should forward to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the supplier supported by order confirmation in writing by the supplier or their photo copies complete in all respects together with two photo copies of the relevant valid import licence as also two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(ii) If the contract documents "Request for issue of A/P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) TCM Section will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAAA and the Embassy of India, Tokyo.

IV(iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo the importer, importer's Bank in India and TCM Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV(iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importers' Bank in India and the CAA&A.

IV(v) The foreign supplier shall, after affecting shipment, present through his bankers the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the supplier through his bankers.

IV(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

#### Section V—Responsibility for rupee deposit

V(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the supplier along with interest charges thereon calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign Supplier to the date of

actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76, dated 12-10-1976 the exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K—Deposits and Advances—843 Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad—Purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1978-79—(Yen 2.9 billion Grand Aid)

V(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- Date of payment to the foreign supplier.
- The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAAA indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

NOTE :—Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAAA, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned banks in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

#### Section VI.—Miscellaneous provisions

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence.—The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.—The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes.—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure—I under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VI(iv) Future Instructions.—The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1978-79 from Japan.

VI(v) Breach or violation.—Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

#### VI(vi) List of Annexures :—

Annexure I—List of eligible source countries.

Annexure II—List of eligible commodities

Annexure III—Form of Request for issue of Authorisation to Pay (A/P).

Annexure IV—Form of letter of Authorisation to Pay (A/P)

Annexure V—Detailed procedure for procurement.

#### ANNEXURE I

Ref : Section 1—Para 1(v)

#### LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

##### A. OECD Countries

Australia

Austria

Belgium

Canada

Denmark

Finland

France

The Federal Republic of Germany

Greece

Iceland

Ireland

Italy

Japan

Luxembourg

the Netherlands

New Zealand

Norway

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

The United Kingdom and the United States

<b>B. Developing Countries &amp; Territories</b>		<b>Senegal</b>
(b1) Non-O.P.E.C. Developing Countries		<b>Seychelles</b>
I. AFRICA, Nor't of Sahara		<b>Sierra Leone</b>
Egypt		<b>Somalia</b>
Morocco		<b>Sudan</b>
Tunisia		<b>Swaziland</b>
II. AFRICA, South of Sahara		
Angola		<b>Terro. Afars and Issas</b>
Botswana		<b>Tago</b>
Burundi		<b>Uganda</b>
Cameroon		<b>Un. Rep. of Tanazania</b>
Cape Verde Islands		<b>Upper Volta</b>
Central African Rep		<b>Zaire Republic</b>
Chad		<b>Zambia</b>
Comoro Islands		
Congo, People's Republic of Dahomay (1)		(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.
Equatorial Guinea		
Ethiopia		(2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.
Gambia		
Ghana		(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St. Eustacit St. Martin (Southern Part).
Guinea		
Ivory Coast		<b>III. AMERICA, North and Cent.</b>
Kenya		<b>Bahamas</b>
Lesotho		<b>Barbodoses</b>
Liberia		<b>Belize</b>
Malagasy Republic		<b>Bermuda</b>
Malawi		<b>Costa Rica</b>
Mali		<b>Cuba</b>
Mauritania		<b>Dominican Republic</b>
Mauritius		<b>El Salvador</b>
Mozambique		<b>Guadeloupe</b>
Niger		<b>Guatemala</b>
Portuguese Guinea		<b>Haiti</b>
Reunion		<b>Honduras</b>
Rhodesia		<b>Jamaica</b>
Rwanda		<b>Martinique</b>
St. Helena and dep (2)		<b>Mexico</b>
Sao Tome and Principee		<b>Netherlands A. tiles</b>

Nicaragua	Hong Kong
Panama	Khmer Republic
St. Pierre & Miquelon	Korea Republic of Laos
Trinidad and Tabago	Macau
West Indies (Br.) n.e.	Malaysia
(a) Associated States (1)	Philippines
(b) Dependencies (2)	Singapore
IV. AMERICA, South	Taiwan
Argentina	Thailand
Bolivia	Timor
Brazil	Vietnam, Rep. of Viet-Nam Dem. Rep.
Chile	(1) Main islands : Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristephe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
Colombia	(2) Main islands ; Montserrat, Gayman, Turks and Caicos and British Virgin Islands.
Falkland Islands	(3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaitwain.
French Guiana	(4) Including Aden and various sultanates and emirates.
Guyana	(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands the Tuamoto-Gambier Group and the Marquesas Islands.
Paraguay	(6) Trust Territory of the Pacific Islands ; Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).
Peru	VIII. OCEANIA
Surinam	Cock Islands
Uruguay	Fiji
V. ASIA, Middle East	Gilbert & Ellice Is.
Bahrain	French Polynesia (5)
Israel	Nauru
Jordan	New Caledonia
Lebanon	New Hebrides (Br. and Fr.)
Oman	Hieu
Syrian Arab Republic	Pacific Islands (US) (6)
United Arab Emirates (3)	Papua New Guinea
Yemen Arab Republic	Solomon Islands (Br.)
Yemen, People's D.R. (4)	Tonga
VI. ASIA, South	Wallis and Futuna
Afghanistan	Western Samoa
Bangladesh	IX. EUROPE
Bhutan	Cyprus
Burma	Gibraltar
Maldives	Greece
Nepal	Malta S
Pakistan	
Sri Lanka	
VII. ASIA, Far East	
Bornei	

Spain	9 Machinery and equipment for the Bombay High Offshore Development Project
Turkey	
Yugoslavia	10 Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon

## (b2) Member or Associate Countries of OPEC

Algeria

Bolivia

Libyan Arab Republic

Gabon

Nigeria

Ecuador

Venezuela

Iran

Iraq

Kuwait

Qatar

Saudi Arabia

Abu Dhabi

Indonesia

ANNEXURE III

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,  
 Ministry of Finance,  
 Department of Economic Affairs,  
 UCO Bank Building, 1st Floor,  
 Parliament Street,  
 New Delhi-110001

Subject —Import from Japan under the Japanese Grant Aid  
 of Yen 29 billion for 1978-79.

Sir,

In connection with the import of . . . from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India Tokyo in favour of the Supplier concerned —

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods

(f) Gross C&F value of contract (in Yen)

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.

(h) Net C&F Value (in Yen) for which the A/P is required

(i) Name and date of the contract with Suppliers.

## ANNEXURE II

## ELIGIBLE COMMODITY LIST

- 1 Rolls
- 2 Steel including special steel & alloy steel
- 3 Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors
- 4 Chemicals
- 5 Spares, components and raw materials for Indo-Japanese Joint Ventures
- 6 Components, attachments and spares for power tillers
- 7 Machinery, components attachments, spares and raw materials
- 8 Machinery and equipment for the National Small Industries Corporation of India

(j) Name and Address of the Supplier and attach an eligibility certificate (in duplicate)

(k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expected date of completion of deliveries.

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transhipment/partshipment permitted or not permitted).

(o) Name and Address of the Importer's bank in India.

(p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No. date and value of such contract.

Yours faithfully,

4. The banking charges including charges for handling documents, if any, payable to you by the importer will also be settled directly by the importer's bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendments to A/P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A/P will remain valid upto \_\_\_\_\_.

Yours faithfully,  
Accounts Officer

Copy forwarded to: —

1. Importer \_\_\_\_\_ with reference to their letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.

2. Importer's Banker \_\_\_\_\_. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15% per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e., the day on which payment is made to the Japanese Supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the

No.

ANNEXURE IV

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)  
New Delhi, the

To

The Bank of India,  
Tokyo Branch  
Tokyo (Japan).

Subject :—Import under Japanese Grant Aid for Yen 2.9 billion Issue of Authorisation to pay

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 13-3-1979 entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen \_\_\_\_\_ to M/s \_\_\_\_\_ (as per details given in the Appendix).

2. Please advise the Contractor of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy each of this advice to the Government of Japan, importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is K-Deposits & Advances-843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan for 1978-79—(Yen 2.9 billion Grant Aid).

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalent are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

#### 4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TCM) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer,

#### ANNEXURE V

#### Guidelines for Procurement of Commodities under Japanese Grant Aid

##### I. Introduction more

The proceeds of the Grant Aid of Yen 2.9 billion extended by the Government of Japan shall be used with due attention to efficiency and non-discrimination among the eligible source countries for procurement of commodities and services incidental thereto in accordance with the procurement procedures set out in this guide lines.

##### II. Selection of Procurement Procedure

The following procedures shall be applicable to the procurement of Listed Commodities under the Grant Aid:

- (1) Formal Open International Tendering.
- (2) Formal Selective International Tendering.
- (3) Informal International Competitive Procurement.
- (4) Direct Purchases.

(a) In the case of the procurement by the government and/or a government agency, Formal Open International tendering or Formal Selective International Tendering shall be applied.

(b) In case of non-government procurement, any of the procedures mentioned above may be applied.

(c) It is, however, possible under this Grant Aid to accept the procurement through Informal International Competitive Procurement or Direct Purchases in the following cases.

- (i) Where the amount of a proposed contract does not exceed 300,000,000.—, US Dollar 1,500,000.— or Pound Sterling 800,000.—, in terms of currency of the contract.
- (ii) Where the number of qualified suppliers is limited.
- (iii) Where purchase of a commodity by reference to a particular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the inter-changeability or standardization of equipment, or because of special design requirements.
- (iv) Where either procedure (1) or procedure (2) by the reason other than the case (i), (ii) and (iii) above (e.g. in case of emergency procurement) is inapplicable.

(d) In any case mentioned above, Importer shall get a confirmation of the Borrower concerning the eligibility of procurement in accordance with the procurement procedure set forth in this Section 1-3.

##### III. Conditions of Contract

Any contract to be financed under this Grant Aid shall fulfill the following conditions.

###### 1. Conditions of Commodities

As the use of this Grant Aid is limited to financing expenditures for Listed Commodities produced in the eligible source countries, the subject items of the Contract shall be Listed Commodities produced in the eligible source countries and to be shipped to an Indian port from the eligible source countries. If the imported portion from non-eligible source countries is less than thirty per cent (30 per cent) of the fol-

lowing formula, Listed Commodities will be financed even if the imported portion from non-eligible source countries is included as a part of the Listed Commodities in the items of the Contract Formula mentioned above:

Imported Price + Import Duty  
----- X 100

Supplier's FOB Price

## 2. Conditions of Supplier:

The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered in the eligible source countries.

## 3. Conditions of Importer:

The procurement of any Commodities by the armed forces or their affiliated organizations of India shall not be eligible under the Loan.

## 4. Denomination of Currency:

The Contract shall be fixed and payable in Japanese Yen, United States Dollar, or Sterling Pound without any fraction less than one Yen (Y 1.00), One cent (C 1.00) of One Penny (d. 1.00) respectively.

## 5. Standard Form of Contract

(a) The following items shall be inserted in the Contract to be financed under this Grant Aid:

- (1) Name and Nationality of Supplier and Importer
- (2) Number and Date of the Contract
- (3) Name and Origin of the Commodities
- (4) Contract Price and Quantity
- (5) Payment Terms
- (6) Delivery and Shipment Schedule
- (7) Other General Regulations

(b) The Contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies, are also acceptable.

(c) The following statement of eligibility by the Supplier shall be added to each contract:

"I (We) hereby state that my (our) company has been registered in \_\_\_\_\_ (eligible source country)."

## 6. Payment:

Each payment shall be made on and after the date of signing of the Grant Aid i.e. 17th March, 1979.

In principle, the full amount of a shipment shall be paid to the supplier on cash basis at each time of presentation of the relative shipping documents to the Bank of India, Tokyo.

## IV. International Tendering

When International Tendering is applied, the procurement shall be made in accordance with the following principles, among others:

### 1. Advertising:

On all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

### 2. Time Interval Between Invitation and Submission of Bids:

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for

international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

### 3. Bid Opening Procedures:

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

### 4. Bid Bonds or Guarantees:

In the case of bidding, bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement, but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

### 5. Standards:

If national standards with which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

### 6. Use of Brand Names:

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features.

In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

### 7. Guarantees and Performance Bonds:

Bidding documents may require some form of surety for guarantees, if necessary. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond.

### 8. Liquidated Damages:

Liquidated damages clauses, if necessary, should be included in bidding documents when delays in delivery will result in extra expenditures, loss of revenues or loss of other benefits to the Importer.

### 9. Force Majeure:

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

### 10. Settlement of Disputes:

Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the Inter-

national Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas Supplier.

#### 11. Evaluation :

#### APPENDIX II TO DEPARTMENT OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 49 ITC (PN)/79 DATED 24-9-1979.

#### LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF PRIVATE SECTOR IMPORTS UNDER THE JAPANESE GRANT AID OF YEN 2.9 BILLION FOR 1978-79 EXTENDED BY THE GOVERNMENT OF JAPAN

##### Section I—General Conditions :

I(i) The Japanese Grand Aid of Yen 2.9 billion extended by the Government of Japan is untied in favour of CECD and developing countries. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries, enumerated in the list at Annexure I which will be the eligible source countries under this Grant. However, if commodities imported under the licence contain components originating from a non eligible source country or countries, it should be ensured by the importer, while negotiating a supply contract, that the total c.i.f. cost, including import duties, of such components imported into the country of the supply contract is less than 30 per cent of the f.o.b. value of the supply contract. In such a case, a certificate to this effect should be obtained from suppliers and attached to the supply contract. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure II.

I(ii) The licence will bear the supercription "Yen 2.9 billion Japanese Grant Aid for 1978-79". The licence code for the first and second suffix will be "S/N". These will also be repeated in the letter from the CCI&F forwarding the import licence.

I(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payment however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the Licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (TCM Section) in the matter.

I(v) Firm order must be placed on CIF or on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan or in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary, Department of Economic Affairs (TCM Section) Ministry of Finance, North Block, New Delhi within 4 months from the date of issue of the import licence. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the letter of purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas Suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

I(vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, TCM Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(v) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merits by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of this import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (TCM Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 30-6-1981.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract :

II(i) (a) The value of the contract should be expressed in Yen or US Dollars or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The FOB cost, insurance and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) For individual imports not exceeding Yen 300 million or US \$ 1,500,000 or £ 800,000 in value (exclusive of Indian agents commission) the licensee is free to effect purchases directly from the suppliers without recourse to international tender enquiries from the countries listed in Annexure-I.

II(iii) Where, however, the supply contracts exceed the limit prescribed in II (ii) above in value (exclusive of Indian agents commission), any one of the following procedures for procurement should be rigidly followed :

(a) Formal Open International Tendering

(b) Formal selective International Tendering

(c) Informal International Competitive Procurement

II(iv) Any reference to International Tendering or International Procurement will mean tendering or procurement, as the case may be, from the eligible source countries.

The above procedure may be relaxed in favour of Informal Competitive procurement or Direct purchase where—

1. a number of qualified suppliers exist in one particular country or in a limited number of countries.

2. purchase of a commodity by reference to a particular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the interchangeability or standardisation of equipment or because of special design requirement.

3. Purchases are in the category of emergency procurement.

The licensee is therefore advised that in case where the procedure at (a) and (b) of para II (iii) above cannot be taken recourse to, a reference to the Department of Economic Affairs shall have to be made who will consider each such case on merits.

II(v) Where Formal Open International Tendering is resorted to, the following points should be borne in mind :—

(a) Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

(b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

(c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(vi) Only one contract should be entered into for the full value of the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

## II(vii) Eligibility of Supplier

The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person governed substantially by nationals of the eligible countries.

Section III: The following provision should be specifically incorporated in the supply contract:—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 17th March, 1979 between the Government of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 2.9 billion for 1978-79 and will be subject to the approval of the Government of India.

III(ii) Payments to the suppliers shall be made through an "Authorisation to pay" (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1978-79.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where the suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, atleast four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

III(v) A certificate in the form indicated below:—

"I (We) hereby state that my (our) Company has been registered in.....(eligible source country) and is governed by nationals of the eligible source countries or juridical persons registered and incorporated in the eligible source Countries".

Section—IV Detailed Procedure for procurement and finalisation of supply contract has been indicated in Annexure-V

Section—V Contract Approval by Government of India

V(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward to the Under Secretary, (TCA Section), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the Overseas Suppliers supported by order confirmation in writing by the Overseas Supplier or their photo-copies, complete in all respects, together with two photo-copies of the relevant valid import licence and also two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annexure III, accompanied by a Bank Guarantee in the form prescribed in Annexure—VI duly adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamp Act.

Where supply contract is based on formal Open International Tendering or Formal Selective International Tendering, a certificate to the following effect should be furnished in duplicate:—

- (i) Name of the Newspapers in which the bid specification was published;
- (ii) Name of parties who quoted against the tender enquiry;
- (iii) the reason for selecting a particular offer indicating whether it is the lowest technically suitable bid.

V(ii) Bank Guarantee—Amount for which it should be executed.

The Bank Guarantee should be for an amount representing the rupee equivalent of the foreign currency amount for which the Authorisation to pay (A/P) is sought plus interest and other charges as mentioned in Annexure—VI. The rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue and prevailing on the date of issue of the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC (PN)/74 dated the 6th June, 1974 issued by the CCI&E.

This rate is meant only for the purpose of arriving at the value of the Bank Guarantee to be furnished by the licensee. For the purpose of making rupee deposits into Government account towards the cost of imports, the rupee equivalent will have to be worked out in the manner indicated in Section VII below.

V(iii) If the contract documents, Request for issue of 'A/P', the Bank Guarantee and other connected documents are found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, TCM Section will approve the contract and arrange to send one set of the documents to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, UCO Bank Building, 1st Floor Parliament Street, New Delhi, and Embassy of India, Tokyo.

Section VI—Payment to the Overseas Suppliers—A/P.

(i) On receipt of the documents mentioned in Section V (iii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure III for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and T.C.M. Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

VI(ii) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA & A.

VI(iii) The foreign supplier shall, after affecting shipment, present through his bankers the documents specified in the A/P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the supplier through his bankers.

VI(iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's Account.

Section VII—Responsibility for rupee deposit :

VII(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure—III who should release these negotiable sets of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the supplier alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 9% per annum for the first thirty days and at 15% for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-74 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public

Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad-purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1978-79. —(Yen 2.9 billion Grant Aid)

VII(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

VII(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the Importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the foreign supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note: Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VII(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

VII(v) After the obligations in terms of the Bank Guarantee and the Authorisation issued by the CAA&A in the Ministry of Finance are fulfilled, the concerned Bank in India can apply to the CAA&A for the release of bank guarantee. The application for this purpose be made in the form laid down in Annexure—VII.

#### Section—VIII Miscellaneous provisions

##### VIII(i) Reports on the utilisation of the import licence

The importer should send a monthly report after the A/P has been issued regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

##### VIII(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

##### VIII(iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

##### VIII(iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1978-79 from Japan.

## VIII(v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

## VIII(vi) List of Annexures :

Annexure I : List of eligible source countries

Annexure II : List of eligible commodities

Annexure III : Form of request for issue of Authorisation to Pay (A/P)

Annexure IV : Form of letters of Authorisation to Pay (A/P)

Annexure V : Detailed procedure for procurement

Annexure VI : Form of Guarantee Bond

Annexure VII : Form of Application for release of Bank Guarantee.

Norway

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

The United Kingdom and  
The United States.

## B Developing Countries &amp; Territories

## (b) Non-O.P.E.C. Developing Countries

## I. Africa North of Sahara

Egypt

Morocco

Tunisia

## II. Africa, South of Sahara

Angola

Botswana

Burundi

Cameroon

Cape Verde Islands

Central African Rep.

Chad

Comoro Islands

Congo, People's Republic of Dahomey (1)

Equatorial Guinea

Ethiopia

Gambia

Ghana

Guinea

Ivory Coast

Kenya

Lesotho

Liberia

Malagasy Republic

## LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

## A OECD Countries

Australia

Austria

Belgium

Canada

Denmark

Finland

France

The Federal Republic of Germany

Greece

Iceland

Ireland

Italy

Japan

Luxembourg

The Netherlands

New Zealand

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

Malawi	El Salvador
Mali	Guadeloupe
Mauritania	Guatemala
Mauritius	Haiti
Mozambique	Honduras
Niger	Jamaica
Portuguese Guinea	Martinique
Reunion	Mexico
Rhodesia	Netherlands Antilles
Rwanda	Nicaragua
St. Helena and dep (2)	Panama
Sao Tome and Principe	St. Pierre & Miquelon
Senegal	Trinidad and Tabago
Seychelles	West Indies (Br.) n.i.e.
Sierra Leone	(a) Associated States (1)
Somalia	(b) Dependencies (2)
Sudan	IV. America, South

Swaziland	Argentina
Terro. Afars and Issas	Bolivia
Tago	Brazil
Uganda	Chile
Un. Rep. of Tanzania	Colombia
Upper Volta	Falkland Islands
Zaire Republic	French Guiana
Zambia.	Guyana
III. America, North and Cent.	Paraguay

Bahamas	Peru
Barbados	Surinam
Belize	Uruguay
Bermuda	V. Asia, Middle East
Costa Rica	Bahrain
Cuba	Israel
Dominican Republic	Jordan

(2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius, St. Martin (Southern Part).

Yemen Arab Republic	Gilbert & Ellice Is.	
Yemen, People's D.R. (4)	French Polynesia (5)	
<b>VI. Asia, South</b>		
Afghanistan	Nauru	
Bangladesh	New Caledonia	
Bhutan	New Hebrides (Br. and Fr.)	
Burma	Hieu	
Maldives	Pacific Islands (US) (6)	
Nepal	Papua New Guinea	
Pakistan	Solomon Islands (Br.)	
Sri Lanka	Tonga	
<b>VII. Asia, Far East</b>		
Borneo	Wallis and Futuna	
Hong Kong	Western Samoa	
Khmer Republic	<b>IX. EUROPE</b>	
Korea, Republic of	Cyprus	
Laos	Gibraltar	
Macao	Greece	
Malaysia	Malta S	
Philippines	Spain	
Singapore	Turkey	
Taiwan	Yugoslavia	
Thailand	(b2) Member or Associate Countries of OPEC	
Timor	Algeria	
Vietnam, Rep. of	Bolivia	
Viet-Nam Dem. Rep.	Libyan Arab Republic	
<b>VII. OCEANIA</b>		
Cock Islands	Gabon	
Fiji	Nigeria	

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands: Caroline Islands, Marshal Islands and Marine Islands (except Guam).

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

## ANNEXURE-II

## ELIGIBLE COMMODITY LIST

1. Rolls
2. Steel including special steel and alloy steel
3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors
4. Chemicals
5. Spares, components and raw materials for Indo-Japanese Joint Ventures
6. Components, attachments and spares for power tillers
7. Machinery, components, attachments, spares and raw materials
8. Machinery and equipment for the National Small Industries Corporation of India
9. Machinery and equipment for the Bombay High Offshore Development Project
10. Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon.

## ANNEXURE-III

**"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION  
TO PAY"**

No

To

The Controller of Aid Accounts & Audit.

Ministry of Finance,

Department of Economic Affairs,

UCO Bank Building, 1st Floor,

Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject :—Imports from Japan under the Japanese Grant Aid of 2.9 billion for 1978-79

Sir,

In connection with the import from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

- (a) Name and address of the Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Gross C&F value of contract (in Yen).
- (g) Amount of Indian agt. & commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.
- (h) Net C&F Value (in Yen) for which the A/P is required.
- (i) Name and date of the contract with Suppliers.
- (j) Name and Address of the Supplier and attach an eligible certificate (in duplicate).
- (k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (indicate if transhipment/part-shipment permitted or not permitted).
- (o) Name and Address of the Importer's bank in India.
- (p) Number, date and value of the Bank Guarantee (s) indicating the period(s) upto which the same is (are) valid.
- (q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No., date and value of such contract.

Yours faithfully,

## ANNEXURE-IV

No.

Government of India  
MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,  
Tokyo Branch,  
Tokyo (Japan).

Subject :—Import under Japanese Grant Aid for Yen 2.9 billion Issue of Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 13-3-1979 entered into with your Bank, you are

hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen \_\_\_\_\_ to M/s. \_\_\_\_\_ (as per details given in the Appendix).

2. Please advise the Contractor of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy each of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. The banking charges including charges for handling documents if any, payable to you by the importer will also be settled directly by the importer's bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendments to A/P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A/P will remain valid upto \_\_\_\_\_

Yours faithfully,

Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer \_\_\_\_\_ with reference to their letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_

2. Importer's Banker \_\_\_\_\_ They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76, dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese Supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I. Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)/68, dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71, dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)/76, dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is 'K-Deposits & Advances -843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan for 1978-79 (Yen 2.9 billion Grant Aid)'.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71, dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TCM) Ministry of Finance Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer

#### ANNEXURE—V

##### Guidelines for Procurement of Commodities under Japanese Grant Aid

###### I. Introduction

The proceeds of the Grant Aid of Yen 2.9 billion extended by the Government of Japan shall be used with due attention to efficiency and non-discrimination among the eligible source countries for procurement of commodities and services incidental thereto in accordance with the procurement procedures set out in this Guidelines.

###### II. Selection of Procurement Procedure

The following procedures shall be applicable to the procurement of Listed Commodities under the Grant Aid :—

- (1) Formal Open International Tendering
- (2) Formal Selective International Tendering
- (3) Informal International Competitive Procurement
- (4) Direct Purchases.

(a) In the case of the procurement by the government and/or a government agency, Formal Open International tendering or Formal Selective International Tendering shall be applied.

(b) In case of non-government procurement, any of the procedures mentioned above may be applied.

(c) It is, however, possible under this Grant Aid to accept the procurement through Informal International Competitive Procurement or Direct Purchases in the following cases :—

- (i) Where the amount of a proposed contract does not exceed Y 300,000,000.—, US \$ 1,500,000.—or Pound Sterling 800,000.—in terms of currency of the contract
- (ii) Where the number of qualified suppliers is limited.

(iii) Where purchase of a commodity by reference to a particular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the inter-changeability or standardization of equipment or because of special design requirements.

(iv) Where either procedure (1) or procedure (2) by the reason other than the case (i), (ii) and (iii) above (e.g. in case of emergency procurement) is inapplicable.

(d) In any case mentioned above, Importer shall get a confirmation of the Borrower concerning the eligibility of procurement in accordance with the procurement procedure set forth in this Section 1-3.

### III. Conditions of Contract

Any contract to be financed under this Grant Aid shall fulfill the following conditions.

#### 1. Conditions of Commodities :

As the use of this Grant Aid is limited to financing expenditures for Listed Commodities produced in the eligible source countries, the subject items of the Contract shall be Listed Commodities produced in the eligible source countries and to be shipped to an Indian port from the eligible source countries. If the imported portion from non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) of the following formula, Listed Commodities will be financed even if the imported portion from non-eligible source countries is included as a part of the Listed Commodities in the items of the Contract Formula mentioned above :

$$\frac{\text{Imported Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

#### 2. Conditions of Supplier :

The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered in the eligible source countries.

#### 3. Conditions of Importer :

The procurement of any Commodities by the armed forces or their affiliated organizations of India shall not be eligible under the Loan.

#### 4. Denomination of Currency :

The Contract shall be fixed and payable in Japanese Yen, United States Dollar, or Sterling Pound without any fraction less than one Yen (Y 1.00), One cent (c 1.00) or One Penny (d. 1.00) respectively.

#### 5. Standard Form of Contract :

(a) The following items shall be inserted in the Contract to be financed under this Grant Aid :—

(1) Name and Nationality of Supplier and Importer

(2) Number and Date of the Contract

(3) Name and Origin of the Commodities

#### (4) Contract Price and Quantity

#### (5) Payment Terms

#### (6) Delivery and Shipment Schedule

#### (7) Other General Regulations

(b) The Contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies, are also acceptable.

(c) The following statement of eligibility by the Supplier shall be added to each contract :—

"I (We) hereby state that my (our) company has been registered in \_\_\_\_\_ (eligible source country)."

#### 6. Payment :

Each payment shall be made on and after the date of signing of the Grant Aid i.e. 17 March, 1979.

In principle, the full amount of a shipment shall be paid to the supplier on cash basis at each time of presentation of the relative shipping documents to the Bank of India, Tokyo.

### IV. International Tendering :

When International Tendering is applied, the procurement shall be made in accordance with the following principles, among others.

#### 1. Advertising :

On all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

#### 2. Time Interval Between Invitation and Submission of Bids :

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

#### 3. Bid Opening Procedures :

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

#### 4. Bid Bonds or Guarantees :

In the case of bidding, bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement, but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

## 5. Standards :

If national standards with which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

## 6. Use of Brand Names :

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features.

In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

## 7. Guarantees and Performance Bonds :

Bidding documents may require some form of surety for guarantees, if necessary. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond.

## 8. Liquidated Damages :

Liquidated damages clauses, if necessary, should be included in bidding documents when delays in delivery will result in extra expenditures, loss of revenues or loss of other benefits to the Importer.

## 9. Force Majeure :

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

## 10. Settlement of Disputes :

Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas Supplier.

## 11. Evaluation

[Ref. Section V—Para V(ii)]

## GUARANTEE BOND

To

The President of India

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Yens/US Dollars and £ Sterling for the import of \_\_\_\_\_ by \_\_\_\_\_ (hereinafter called the 'importer') against the import licence No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ issued under the terms and conditions of Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion, we \_\_\_\_\_ Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit, the amounts of disbursements made by the Bank of India, Tokyo converted at the prevailing composite rate of conversion laid down in CCI&E's Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-76 or as notified from time to time in Public Notices/A.D. Circulars within ten days of the receipt of advice of payments for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Accounts as indicated by the Government of India under the said Grant Aid together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the overseas supplier to and inclusive of the date of deposit of Rupee equivalent for credit to the Government account. The negotiable set of import documents received from the Bank of India, Tokyo, will be released to the Importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the \_\_\_\_\_ (Bank), also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceeding Rs. \_\_\_\_\_, or any part thereof, for the time being due and payable by the importer, together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned from the date of the payment to the overseas supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us \_\_\_\_\_ (Bank), shall be final and binding on us \_\_\_\_\_ (Bank).

3. We, \_\_\_\_\_ (Bank), further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of chance in the composite rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change take place, in proportion to this change.

4. We, \_\_\_\_\_(Bank), further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee, have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the \_\_\_\_\_ (Bank) and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time of the powers exercisable by it against the importer and the \_\_\_\_\_ (Bank) shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matter aforesaid or by reasons of time being given to the importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any other matter or thing the Government to the importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the \_\_\_\_\_ (Bank) from its such liability.

6. We \_\_\_\_\_ (Bank), lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with provision consent of the Government in writing.

7. Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs. \_\_\_\_\_ (plus interest and all banking charges, not expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount), and this guarantee shall remain in force till\*\* the date of \_\_\_\_\_ (month) 19\_\_\_\_\_. Unless claims under this bond/guarantee are made in writing within six months of this date and unless suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter, i.e. upto \_\_\_\_\_ all Government's rights under this bond/guarantee shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Date the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_\_  
for \_\_\_\_\_ (Bank)

Accepted for and on behalf of the  
President of India by Shri \_\_\_\_\_  
(Name and Designation)

**Signature**

**Signature**

\*\*This date shall be arrived at by adding one month to the date up to which the Letter of Credit is required to be kept valid.

Note : The value of the stamped paper on which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

## ANNEXURE—VII

[Section VII-Para VII (v)]

Form of Application for release of Bank Guarantee

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,  
Ministry of Finance,  
Department of Economic Affairs,  
UCO Bank Building, 1st Floor,  
Parliament Street, New Delhi-1.

Sir,

We are furnishing below detailed information on the rupee deposits made by us in the discharge of our obligations under Bank Guarantee No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ for an amount of Rs. \_\_\_\_\_ with the request that the same may be released and returned to us.

- 1 The name and full address of the importer/licencee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished.
2. The import licence No., date, value, brief description of the equipment and/or commodities allowed for import thereunder.
3. Particulars of the authorisation (s) obtained from the Ministry of Finance (to be given separately for each authorisation).
  - (a) Letter No and date.
  - (b) Amount of Authorisation.
  - (c) Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion.
4. Particulars of imports and rupee deposits made (to be given separately for each Authorisation).
  - (a) Amount of Invo. (net) in Yen /US \$ / £.
  - (b) Amount of Rupee deposit.
  - (c) Relative challan No. and date and the name of Treasury/Bank.
  - (d) If by demand draft, No. and date of the demand draft No. and date of the Letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Delhi.
5. Amount utilised and balance utilised (Yen/US \$ / £) in each Authorisation.

II. We certify that :—

(1) \*The balance amount of Yen \_\_\_\_\_ available in the authorisation(s) given by the Ministry of Finance has not been utilised/will not be utilised.

\*Whichever is applicable.

(2) Our obligation under the Bank Guarantee in question have been fully discharged.

IV. We request that the bank guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

III. We confirm that the interest and banking charges of the Bank of India, Tokyo and charges, if any, of overseas suppliers Bankers relative to this transaction have been remitted by us to the Bank of India, Tokyo.

Yours faithfully,  
Authorised Agent for and on  
behalf of the Bank.